facebook.com/thebharatshri
twitter.com/thebharatshri
website thebharatshri

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम

भारत श्री

राष्ट्रीय हिंदी साप्ताहिक

सोमवार, 15 दिसंबर 2025 ● वर्ष 7 ● अंक 22 ● मूल्यः 5 रुपए

बीमारी से विश्वविजेता बनने...

आदिकाल से है सनातन धर्म

पेज-10-11

सद्गुरु वाणी

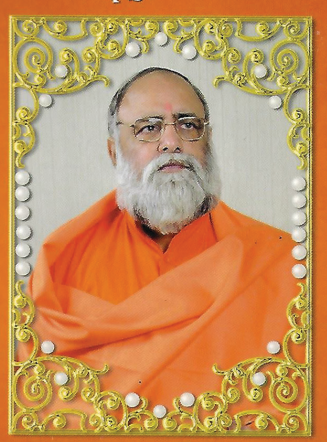

दिव्य पाठ से मस्तिष्क जाग्रत अवस्था में आ जाता है। मस्तिष्क में ज्ञान का प्रवाह विद्युत की भांति तरंगित हो उठता है। इसके विवेक को अकल्पनीय ऊर्जा मिलती है।

●

तथाकथित गुरु और संत हमें चिंतन नहीं देते बल्कि भयभीत करके चिंता दे देते हैं। सच्चा गुरु वही है जो मनुष्य को चिंताओं और भय से मुक्त करे।

●

भौतिक संपन्नता के बावजूद पश्चिम जगत के देश दुखी हैं। केवल अध्यात्म और दिव्या पाठ ही सच्चा सुख प्रदान करने में सक्षम हैं।

पीएम मोदी की जॉर्डन यात्रा

मुस्लिम बहुल देश में कितने हिंदू, कितना मजबूत है भारत का रिश्ता

@ भारतश्री ब्यूरो

अम्मान की सड़कों पर उस वक्त अलग ही उत्साह दिखा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन की राजधानी पहुंचे। हवाई अड्डे से लेकर कार्यक्रम स्थल तक भारतीय समुदाय के लोग तिरंगे के साथ मौजूद थे। 'भारत माता की जय' और 'मोदी–मोदी' के नारों से माहौल गूंज उठा। पश्चिम एशिया के इस छोटे लेकिन रणनीतिक रूप से अहम देश में भारतीयों की मौजूदगी और गर्मजोशी भरा स्वागत कई सवालों को जन्म देता है। जॉर्डन में भारतीय समुदाय कितना बड़ा है। यहां हिंदुओं की आबादी कितनी है। कौन सा धर्म सबसे प्रभावशाली है और भारत–जॉर्डन संबंधों की असली तस्वीर क्या है।

जॉर्डन की जनसंख्या और धार्मिक संरचना

यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के अनुसार, वर्ष 2022 तक जॉर्डन की कुल आबादी करीब 1.1 करोड़ थी। यह देश धार्मिक दृष्टि से लगभग एकरूप है। जॉर्डन एक मुस्लिम बहुल देश है, जहां करीब 97.1 प्रतिशत आबादी सुन्नी मुसलमानों की है। इसके बाद ईसाई समुदाय आता है, जो कुल आबादी का लगभग 2.1 प्रतिशत है।हिंदुओं की संख्या यहां बहुत कम है। आंकड़ों के अनुसार, जॉर्डन में हिंदू आबादी एक प्रतिशत से भी कम है। यही स्थिति बौद्ध, दूज और बहाई समुदायों की भी है। हालांकि संख्या कम होने के बावजूद भारतीय मूल के लोग व्यापार, स्वास्थ्य, आईटी और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पर भारतीय समुदाय पूरे जोश के साथ सामने आया।

जॉर्डन में हिंदू कौन हैं

जॉर्डन में रहने वाले हिंदू मूलतः भारत से गए प्रोफेशनल्स और श्रमिक हैं। इनमें इंजीनियर, डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन और छोटे कारोबारी शामिल हैं। यहां कोई बड़ा मंदिर या धार्मिक ढांचा नहीं है, लेकिन भारतीय समुदाय अपने त्योहार और परंपराएं सीमित दायरे में मनाता है। भारतीय दूतावास भी समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए समुदाय को जोड़ने का काम करता है।

सत्ता की कमान राजा के हाथों में

जॉर्डन की शासन व्यवस्था राजशाही पर आधारित है। देश की सत्ता पूरी तरह किंग अब्दुल्ला द्वितीय और उनके परिवार के हाथों में है। किंग अब्दुल्ला को पश्चिम एशिया के प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता है। वे सेना से गहरे जुड़े हुए हैं और आम जनता के बीच भी उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है।दुनिया के अमीर राजाओं में शामिल किंग अब्दुल्ला की संपत्ति हजारों करोड़ रुपये आंकी जाती है। आलीशान महल, कारों का संग्रह और मजबूत सैन्य तंत्र उनकी पहचान है। इसके बावजूद जॉर्डन को क्षेत्र में एक स्थिर और संतुलित देश माना जाता है।

क्यों अहम है यह दौरा

मोदी का जॉर्डन दौरा सिर्फ औपचारिक कूटनीति नहीं है। यह पश्चिम एशिया में भारत की बढ़ती भूमिका का संकेत है। जॉर्डन जैसे स्थिर और भरोसेमंद देश के साथ रिश्ते मजबूत करना भारत की विदेश नीति के लिहाज से अहम है।साथ ही, अल्पसंख्यक होने के बावजूद जॉर्डन में भारतीय समुदाय की मौजूदगी यह दिखाती है कि भारतीय प्रवासी जहां भी जाते हैं, अपनी मेहनत और पहचान से सम्मान हासिल करते हैं।अम्मान की सड़कों पर गूंजे नारों और गर्मजोशी भरे स्वागत के बीच यह साफ है कि भारत और जॉर्डन के रिश्ते सिर्फ सरकारों तक सीमित नहीं, बल्कि लोगों के दिलों तक पहुंचे हैं। यही किसी भी कूटनीतिक यात्रा की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है।

भारत–जॉर्डन रिश्तों की मजबूत नींव

प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि यह भारत और जॉर्डन के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर हो रही है। दोनों देशों के संबंध दशकों पुराने हैं और समय के साथ मजबूत हुए हैं।भारत आज जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत जॉर्डन को अनाज, फ्रोजन मीट, पेट्रोलियम उत्पाद, पशु चारा और दवाइयां निर्यात करता है। वहीं जॉर्डन, भारत के लिए फॉस्फेट और पोटाश जैसे उर्वरकों का बड़ा आपूर्तिकर्ता है। भारत में फॉस्फेटिक उर्वरकों की बढ़ती मांग को देखते हुए जॉर्डन में भारतीय निवेश बढ़ने की संभावनाएं भी मजबूत हुई हैं।

समझौतों से खुले नए रास्ते

इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए। नई और नवीकरणीय ऊर्जा में तकनीकी सहयोग, जल संसाधन प्रबंधन, सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम का नवीनीकरण, डिजिटल सहयोग और पेट्रा–एलोरा ट्विनिंग एग्रीमेंट जैसे समझौते इसमें शामिल हैं।इन समझौतों का मकसद सिर्फ कागजी रिश्ते नहीं, बल्कि जमीन पर सहयोग बढ़ाना है। जल संकट से जूझ रहे जॉर्डन के लिए भारत का जल प्रबंधन अनुभव खासा अहम माना जा रहा है।

यूपीआई से जुड़ सकता है जॉर्डन

प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्डन को भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई से जोड़ने का प्रस्ताव भी रखा। अगर यह पहल आगे बढ़ती है, तो दोनों देशों के बीच व्यापार और पर्यटन को बड़ा फायदा मिल सकता है।

MN DIVINE

ORDER ALL TYPES OF :

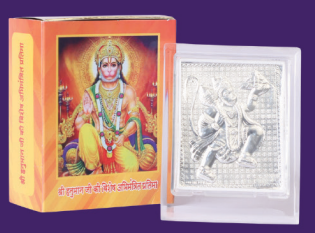

- POOJA SAMAGRI,
- AYURVEDIC MEDICINE
- AND PRATIMA.

NOW GET AT YOUR HOME ON

MNDIVINE.COM

ORDER NOW

https://mndivine.com/

HELPLINE : 9667793986
(10AM TO 6PM, MON-SAT)

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

बीजिंग का नीला आसमान

दिल्ली के लिए सीख या मुश्किल चुनौती?

पुराने दिनों की धुंध: बीजिंग और दिल्ली की प्रदूषण की तुलना

कभी-कभी हम सोचते हैं कि हमारी दिल्ली की हवा कितनी खराब हो गई है, लेकिन एक समय था जब बीजिंग की हवा दिल्ली से भी ज्यादा जहरीली थी। साल 2013 में बीजिंग का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI अक्सर 300 से ऊपर चढ़ जाता था, जो बहुत खतरनाक स्तर है। वहां की सड़कों पर धुंध इतनी घनी होती थी कि लोग मास्क लगाकर सांस लेते थे, और ओलंपिक जैसे बड़े इवेंट के दौरान एथलीटों ने तो यहां तक सोचा कि न आएं। उधर दिल्ली में भी प्रदूषण की समस्या गंभीर थी, लेकिन बीजिंग की तुलना में थोड़ी कम। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, बीजिंग का PM2.5 लेवल 100 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से ज्यादा था, जबकि दिल्ली का करीब 80 के आसपास। दोनों शहरों में कोयला जलाना, फैक्टरियां, गाड़ियां और पराली जलाना मुख्य वजहें थीं। लेकिन 2025 तक आते-आते तस्वीर बदल गई। बीजिंग का सालाना औसत AQI अब 77 रह गया है, जो अच्छा स्तर माना जाता है। वहीं दिल्ली का 129 है, जो अभी भी चिंता की बात है। इस साल जनवरी से अक्टूबर तक दिल्ली में एक भी गंभीर प्रदूषण वाला दिन नहीं आया, और PM2.5 लेवल 83 से घटकर 72 माइक्रोग्राम हो गया। फिर भी, अक्टूबर में पूरे भारत की हवा खराब हुई, जहां 255 शहरों में PM2.5 WHO के मानक से ज्यादा था। ये तुलना बताती है कि प्रदूषण कोई नई समस्या नहीं, बल्कि सही कदमों से इसे काबू किया जा सकता है। बीजिंग ने साबित कर दिया कि अगर इच्छाशक्ति हो, तो धुंध को साफ आसमान में बदला जा सकता है। लेकिन दिल्ली के लिए ये सीख लेना आसान है या नहीं, ये सवाल अभी खड़ा है। दोनों शहरों की आबादी करोड़ों में है, और आर्थिक दबाव भी एक जैसे। फिर भी, बीजिंग की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम भी वैसा ही रास्ता अपना सकते हैं। ये तुलना न सिर्फ आंकड़ों की है, बल्कि लोगों की जिंदगी की भी। बीजिंग में अब बच्चे बिना डर के बाहर खेलते हैं, जबकि दिल्ली में सर्दियों में स्कूल बंद हो जाते हैं। ये बदलाव कैसे आया, ये जानना जरूरी है, क्योंकि इससे भारत को सबक मिल सकता है। कुल मिलाकर, ये इतिहास हमें बताता है कि प्रदूषण से लड़ाई लंबी है, लेकिन जीत संभव है अगर सब मिलकर प्रयास करें।

चीन की मेहनत: बीजिंग ने प्रदूषण से कैसे लड़ा

बीजिंग ने प्रदूषण से लड़ाई को एक मिशन की तरह लिया, और साल 2013 में शुरू किया गया फाइव-ईयर एक्शन प्लान इसकी नींव था। उस समय बीजिंग की हवा इतनी खराब थी कि लोग घरों में कैद हो जाते थे। सरकार ने फैसला किया कि अब बदलाव लाना होगा। सबसे पहले, उन्होंने 3000 कोयला बॉयलर बंद कर दिए, जिससे कोयले का इस्तेमाल 30 प्रतिशत कम हो गया। फैक्टरियों पर सख्त निगरानी रखी गई—जो प्रदूषण फैला रही थीं, उन्हें या तो बंद किया या अपग्रेड किया। इंडस्ट्रीज को शहर से बाहर शिफ्ट किया गया, ताकि हवा साफ रहे। ट्रांसपोर्ट में बड़ा बदलाव आया: डीजल बसों को इलेक्ट्रिक से बदल दिया, और शेनझेन जैसे शहरों में सारी 16000 बसें इलेक्ट्रिक हो गईं। मेट्रो नेटवर्क को 1000 किलोमीटर तक बढ़ाया गया, और गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन लॉटरी सिस्टम से सीमित की गई। साइकिल शेयरिंग को फिर से बढ़ावा दिया, ताकि लोग पैदल या साइकिल से चलें। क्षेत्रीय समन्वय पर जोर दिया—बीजिंग के आसपास के शहरों जैसे तियानजिन और हेबेई में भी एक साथ कदम उठाए गए, क्योंकि प्रदूषण सीमाओं को नहीं मानता। निगरानी के लिए 1500 स्टेशन लगाए गए, और ब्लू स्काई ऐप से लोगों को रीयल-टाइम डेटा मिलने लगा। पेड़ लगाने का अभियान चला, 100 मिलियन पेड़ लगाए गए। ये सब कदम सख्त कानूनों और सजा से चले। जो फैक्टरी नियम तोड़ती, उसे भारी जुर्माना या बंदी हो जाती। सरकार ने पर्यावरण को अधिकारियों की प्रोमोशन से जोड़ा, ताकि सब जिम्मेदार महसूस करें। नतीजा ये हुआ कि 2013 से 2017 तक PM2.5 लेवल 35 प्रतिशत गिर गया। 2024 तक ये कमी 64 प्रतिशत हो गई। लोगों की जिंदगी में सुधार आया—औसत उम्र 4.6 साल बढ़ गई। चीन ने दिखाया कि प्रदूषण से लड़ाई में पैसा लगाना पड़ता है, लेकिन फायदा लंबा चलता है। ये प्रयास सिर्फ शहर तक सीमित नहीं थे, बल्कि पूरे देश की नीति बने। आज बीजिंग की हवा साफ है, और ये मॉडल दुनिया के लिए उदाहरण है। लेकिन ये सफर आसान नहीं था—शुरू में फैक्टरियां बंद होने से नौकरियां गईं, लेकिन सरकार ने नए रोजगार के रास्ते बनाए। ये कहानी बताती है कि इच्छाशक्ति से कुछ भी संभव है।

बीजिंग मॉडल के मुख्य तत्व: सफलता के पीछे की रणनीति

बीजिंग मॉडल की ताकत उसके बहु-आयामी कदमों में है, जो सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं। सबसे बड़ा तत्व था सख्त शासन व्यवस्था—केंद्रीय सरकार ने स्थानीय अधिकारियों को प्रदूषण नियंत्रण से जोड़ा, और उनकी सफलता पर प्रमोशन तय की। इंडस्ट्रीज पर फोकस किया: हजारों पुरानी फैक्टरियां जैसे स्टील मिलें, केमिकल प्लांट और पावर स्टेशन बंद किए गए। जो बचीं, उन्हें क्लीन टेक्नोलॉजी अपनाने को कहा गया। ऊर्जा में बदलाव आया—कोयले पर पाबंदी लगाई, और रिन्यूएबल सोर्स जैसे सोलर और विंड को बढ़ावा दिया। घरेलू हीटिंग में क्लीन फ्यूल लाए, ताकि सर्दियों में धुआं न फैले। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में EVs को पुश दिया—40 प्रतिशत कारें इलेक्ट्रिक बनाने का टारगेट रखा। लो एमिशन जोन बनाए, जहां पुरानी गाड़ियां न घुस सकें। क्षेत्रीय सहयोग जरूरी था, क्योंकि प्रदूषण हवा के साथ दूर तक जाता है। बीजिंग-तियानजिन-हेबेई रीजन में एक साथ प्लानिंग की गई। मॉनिटरिंग सिस्टम मजबूत किया—डेटा पारदर्शी रखा, ताकि लोग जागरूक रहें। कानूनी ढांचा सख्त बनाया, और मार्केट मैकेनिज्म जैसे टैक्स से प्रदूषण कम करने को प्रोत्साहन दिया। नतीजे कमाल के: 2013 से 2021 तक प्रदूषण 42 प्रतिशत कम हुआ। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 54 प्रतिशत, और सल्फर डाइऑक्साइड 83 प्रतिशत गिरा। ये मॉडल सिर्फ तकनीक पर नहीं, बल्कि लोगों की भागीदारी पर टिका। स्कूलों में जागरूकता अभियान चले, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सस्ता बनाया। चुनौतियां भी थीं—आर्थिक नुकसान, लेकिन लंबे समय में फायदा हुआ। विशेषज्ञ कहते हैं कि ये मॉडल इसलिए कामयाब रहा क्योंकि ये निरंतर था, न कि मौसमी। बीजिंग ने दिखाया कि प्रदूषण नियंत्रण आर्थिक विकास को रोकता नहीं, बल्कि मजबूत बनाता है। क्लीन इंडस्ट्रीज से नए जॉब्स बने, और पर्यटन बढ़ा। ये तत्व बताते हैं कि सफलता के लिए समग्र दृष्टिकोण चाहिए—शासन, तकनीक, और समाज सबका मेल।

भारत में बीजिंग मॉडल: लागू करने की संभावनाएं और बाधाएं

बीजिंग मॉडल भारत के लिए प्रेरणा है, लेकिन इसे लागू करना आसान नहीं। दिल्ली में 2025 में बीजिंग जैसा प्लान बन रहा है—इंडस्ट्रीज के लिए PM2.5 लिमिट को 50.6 माइक्रोग्राम से और सख्त करना। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) 2019 से चल रहा है, जो 2026 तक 40 प्रतिशत प्रदूषण कम करने का लक्ष्य रखता है। लेकिन फंड का सिर्फ 29.5 प्रतिशत इस्तेमाल हुआ 2019-2024 तक। बीजिंग से सीख: क्षेत्रीय समन्वय जरूरी। दिल्ली का प्रदूषण पंजाब-हरियाणा की पराली से आता है, तो राज्यों को एक साथ काम करना होगा। EVs को पुश देना—भारत में इलेक्ट्रिक बसें बढ़ रही हैं, लेकिन अभी कम। मॉनिटरिंग बेहतर हो सकती है, जैसे रीयल-टाइम ऐप्स। पेड़ लगाना और ग्रीन बेल्ट बनाना आसान कदम हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि राजनीतिक इच्छाशक्ति से सब संभव है। लेकिन चुनौतियां बड़ी हैं: भारत का संघीय ढांचा—केंद्र और राज्य अलग-अलग सोचते हैं। प्रवर्तन कमजोर है, और आर्थिक दबाव से फैक्टरियां विरोध करती हैं। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) मौसमी है, जबकि बीजिंग का प्लान साल भर चला। बायोमास बर्निंग ग्रामीण इलाकों में समस्या है, जहां क्लीन फ्यूल पहुंचना मुश्किल। फिर भी, संभावनाएं हैं—2022 में NCAP से 19.3 प्रतिशत कमी आई। अगर सख्त टारगेट और सजा हो, तो दिल्ली बीजिंग जैसी हो सकती है। ये मॉडल भारत को दिखाता है कि छोटे-छोटे कदम से बड़ा बदलाव आता है, लेकिन धैर्य और एकता चाहिए।

साफ हवा की उम्मीद: भारत का भविष्य

प्रदूषण से लड़ाई में बीजिंग की कहानी हमें आशा देती है कि साफ हवा संभव है। भारत को अब लंबे समय के प्लान बनाने होंगे, जहां पर्यावरण को विकास का हिस्सा बनाया जाए। NCAP को मजबूत करना, फंड बढ़ाना, और लोगों को शामिल करना जरूरी। अगर केंद्र-राज्य मिलकर काम करें, तो दिल्ली की हवा 5 साल में बेहतर हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि बीजिंग मॉडल को भारतीय संदर्भ में ढालना पड़ेगा—जैसे ग्रामीण क्लीन कुकिंग पर फोकस। ये बदलाव सिर्फ हवा के लिए नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के लिए हैं। बीजिंग में साफ हवा से पर्यटन और बिजनेस बढ़ा।

बीमारी से विश्वविजेता बनने तक लियोनेल मेस्सी की कहानी

@ शोभित यादव

दुनिया भर में फुटबॉल किंग कहे जाने वाले लियोनेल मेस्सी का हालिया भारत दौरा एक दशक बाद हुआ। GOAT इंडिया टूर 2025 के तहत मेस्सी कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली पहुंचे और हर जगह लाखों फैंस ने उन्हें देखने के लिए सड़कों और स्टेडियमों को भर दिया। आज जब मेस्सी को दुनिया का सबसे महान फुटबॉलर माना जाता है, तब यह याद रखना जरूरी है कि यह मुकाम उन्हें सहजता से नहीं मिला। उनकी कहानी संघर्ष, धैर्य और जुनून से भरी हुई है। यह सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं, बल्कि उस इंसान की कहानी है जिसने हालात से हार मानने से इनकार कर दिया।लियोनेल आंद्रेस मेस्सी का जन्म 24 जून 1987 को अर्जेंटीना के रोसारियो शहर में हुआ। उनका परिवार साधारण था। पिता फैक्ट्री में काम करते थे और मां घर संभालती थीं। बचपन से ही मेस्सी का झुकाव फुटबॉल की ओर था। गेंद उनके पैरों से जैसे चिपकी रहती थी। गली के बच्चे हों या स्थानीय क्लब, हर कोई इस छोटे कद के लड़के की प्रतिभा को पहचानने लगा था। लेकिन किसे पता था कि यही बच्चा कुछ साल बाद एक गंभीर बीमारी से जूझने वाला है।

जब मेस्सी दस साल के हुए, तब डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी नाम की बीमारी है। इस बीमारी के कारण शरीर का विकास रुक जाता है। मेस्सी की लंबाई बढ़ नहीं रही थी और भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो गए थे। इलाज मौजूद था, लेकिन बेहद महंगा। हर महीने लाखों रुपये का खर्च, जो उनके परिवार के लिए लगभग नामुमकिन था। यह वह दौर था जब मेस्सी का सपना टूट सकता था।कई परिवार ऐसे हालात में हार मान लेते हैं, लेकिन मेस्सी के माता पिता ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हर दरवाजा खटखटाया। स्थानीय क्लबों से मदद मांगी, लेकिन कोई ठोस सहारा नहीं मिला। इस बीच मेस्सी फुटबॉल खेलते रहे। बीमारी के बावजूद उनका खेल कमजोर नहीं पड़ा। मैदान पर उनका आत्मविश्वास वही था। शायद यही जिद और जुनून उनकी किस्मत बदलने वाला था।

जब मेस्सी तेरह साल के हुए, तब उनके जीवन में सबसे बड़ा मोड़ आया। स्पेन के मशहूर क्लब एफसी बार्सिलोना ने उनकी प्रतिभा को पहचाना। क्लब ने न सिर्फ उन्हें अपनी अकादमी ला मासिया में जगह दी, बल्कि उनके इलाज का पूरा खर्च उठाने का फैसला भी किया। यह फैसला मेस्सी और उनके परिवार के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। पूरा परिवार अर्जेंटीना छोड़कर बार्सिलोना आ गया। नए देश, नई भाषा और नई संस्कृति के बीच मेस्सी ने खुद को साबित करने की ठानी।इलाज के साथ साथ मेस्सी का खेल भी निखरने लगा। एफसी बार्सिलोना की अंडर 14 टीम से खेलते हुए उन्होंने जल्दी ही सबका ध्यान खींचा। गेंद पर उनका नियंत्रण, रफ्तार और गोल करने की कला उम्र से कहीं आगे की लगती थी। कोच और साथी खिलाड़ी समझ गए थे कि यह लड़का खास है। धीरे धीरे वह एक टीम से दूसरी टीम में आगे बढ़ते गए।

सत्रह साल की उम्र में मेस्सी ने बार्सिलोना के लिए अपना पहला सीनियर मैच खेला। यह सिर्फ एक डेब्यू नहीं था, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। मैदान पर उतरते ही उन्होंने दिखा दिया कि वह किसी से कम नहीं हैं। जल्द ही वह बार्सिलोना की पहचान बन गए। रोसारियो का वह छोटा सा लड़का अब दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर चमक रहा था।बार्सिलोना के साथ मेस्सी का सफर ऐतिहासिक रहा। सत्रह साल के करियर में उन्होंने क्लब को अनगिनत खिताब दिलाए। दस बार ला लीगा का खिताब, चार बार चैंपियंस लीग, सात बार कोपा डेल रे। आंकड़े सिर्फ ट्रॉफियों तक सीमित नहीं रहे। ला लीगा में सबसे ज्यादा 474 गोल करने का रिकॉर्ड भी मेस्सी के नाम है। हर सीजन में वह खुद को बेहतर बनाते रहे।

व्यक्तिगत उपलब्धियों की बात करें तो मेस्सी ने रिकॉर्ड आठ बैलन डी ओर जीते। यह पुरस्कार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को दिया जाता है। हर बार जब उन्हें यह सम्मान मिला, उन्होंने विनम्रता के साथ स्वीकार किया। कभी घमंड नहीं, कभी दिखावा नहीं। यही बात उन्हें औरों से अलग बनाती है।2021 में मेस्सी ने भारी मन से बार्सिलोना को अलविदा कहा और पेरिस सेंट जर्मेन का हिस्सा बने। वहां दो साल खेलने के बाद उन्होंने अमेरिका की मेजर लीग सॉकर में इंटर मियामी को जॉइन किया। उम्र बढ़ने के बावजूद उनके खेल की चमक कम नहीं हुई। जहां भी गए, स्टेडियम भरे और फुटबॉल को नई पहचान मिली।

फुटबॉल के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मेस्सी का सफर भावनाओं से भरा रहा। कई साल तक यह कहा जाता रहा कि वह देश के लिए ट्रॉफी नहीं जीत पाए। आलोचनाएं होती रहीं। लेकिन मेस्सी चुपचाप खेलते रहे। आखिरकार 2022 में कतर में हुए फीफा वर्ल्ड कप में उन्होंने इतिहास रच दिया। अर्जेंटीना को विश्व चैंपियन बनाया और खुद गोल्डन बॉल जीती। यह जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, बल्कि वर्षों की मेहनत और इंतजार का फल थी।इससे पहले भी वह अर्जेंटीना को कोपा अमेरिका जिताने में अहम भूमिका निभा चुके थे और 2008 बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे थे। अंतरराष्ट्रीय मंच पर उन्होंने हर उस सवाल का जवाब दिया, जो कभी उनकी क्षमता पर उठाए गए थे।

लियोनेल मेस्सी की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। वह सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न हों, अगर इरादा मजबूत हो तो रास्ता निकल ही आता है। वह सिखाती है कि बीमारी, गरीबी या असफलता किसी सपने का अंत नहीं होती। परिवार का साथ, मेहनत और धैर्य किसी भी इंसान को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है।अपार सफलता के बावजूद मेस्सी आज भी जमीन से जुड़े हुए हैं। वह अपने कोचों, साथियों और परिवार का हमेशा जिक्र करते हैं। अपनी मेस्सी फाउंडेशन के जरिए वह शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के लिए काम करते हैं। मैदान के बाहर भी वह लाखों लोगों के लिए प्रेरणा हैं।भारत दौरे के दौरान जब मेस्सी मुस्कुराते हुए फैंस का अभिवादन कर रहे थे, तब हर चेहरे पर वही भाव था, जो किसी अपने को देखकर होता है। शायद इसलिए क्योंकि मेस्सी सिर्फ एक फुटबॉलर नहीं हैं। वह उस सपने का नाम हैं, जो मुश्किलों के बीच भी जिंदा रहता है और एक दिन पूरी दुनिया को प्रेरित करता है।

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

कायस्थ कार्ड और बीजेपी की नई चाल

नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर क्या संदेश देना चाहती है पार्टी

@ मनीष पांडेय

बीजेपी ने आखिरकार तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। लंबे समय से यह कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी जातिगत संतुलन साधने के लिए पिछड़ा वर्ग या दलित समुदाय से किसी चेहरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप सकती है। लेकिन पार्टी ने सबको चौंकाते हुए बिहार के वरिष्ठ विधायक नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। नितिन नबीन कायस्थ समुदाय से आते हैं, और इस फैसले को बीजेपी की एक सोची-समझी सामाजिक और राजनीतिक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।देश में कायस्थों की आबादी भले ही कुल जनसंख्या का एक फीसदी से कुछ ज्यादा मानी जाती हो, लेकिन राजनीतिक, प्रशासनिक और बौद्धिक क्षेत्रों में उनका प्रभाव हमेशा से खास रहा है। अनुमान के मुताबिक देशभर में कायस्थों की संख्या 1.5 से 2 करोड़ के बीच है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में यह समुदाय न सिर्फ संगठित है, बल्कि कई सीटों पर चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता भी रखता है।

मुगलों से अंग्रेजों तक, सत्ता के करीब रहे कायस्थ

इतिहास के पन्नों को पलटें तो कायस्थों की पहचान सिर्फ एक जाति तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक पेशेवर वर्ग के रूप में भी उनकी भूमिका रही है। मुगल काल में और फिर ब्रिटिश शासन के दौरान कायस्थ लेखक, मुंशी-मुनीम, लिपिक और राजस्व व्यवस्था की रीढ़ माने जाते थे। प्रशासनिक कामकाज में उनकी पकड़ मजबूत थी। हालांकि उनका उल्लेख इससे भी पहले, दसवीं-ग्यारहवीं सदी के ग्रंथों में मिलता है।शिक्षा के क्षेत्र में आगे रहने के कारण कायस्थ समाज के लोग धीरे-धीरे उच्च पदों तक पहुंचे। यही वजह रही कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में भी इस समुदाय का प्रभाव साफ दिखाई देता है। आज़ादी के बाद की राजनीति में भी कायस्थों ने अपनी अलग पहचान बनाई।

राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री तक, कायस्थों की विरासत

भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद और देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री कायस्थ समुदाय से ही थे। साहित्य की दुनिया में हरिवंशराय बच्चन और मुंशी प्रेमचंद्र जैसे नाम आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं। विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर, जगदीश चंद्र बोस और सत्येंद्र नाथ बोस ने भारत का नाम दुनिया भर में रोशन किया।स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस, चितरंजन दास, रासबिहारी बोस, खुदीराम बोस और गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे क्रांतिकारी और विचारक भी इसी समाज से जुड़े रहे। यह विरासत आज भी कायस्थ समुदाय की सामाजिक चेतना का आधार मानी जाती है।

बंगाल में कायस्थ फैक्टर और चुनावी गणित

पश्चिम बंगाल में कायस्थों की आबादी 27 लाख से अधिक बताई जाती है। घोष, बोस, दत्ता, गुहा जैसे उपनामों से पहचाने जाने वाले कायस्थ राज्य के लगभग हर हिस्से में फैले हुए हैं। कोलकाता और उसके आसपास इनकी संख्या और प्रभाव दोनों ही काफी ज्यादा हैं।बंगाल की राजनीति में कायस्थ समुदाय को एक पढ़ा-लिखा, संगठित और प्रभावशाली वर्ग माना जाता है। आगामी विधानसभा चुनावों में भी उनके रुख का असर साफ दिख सकता है। बीजेपी लंबे समय से बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है और ऐसे में कायस्थ समाज को साधना उसके लिए अहम माना जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में निर्णायक भूमिका

उत्तर प्रदेश में कायस्थों को लाला भी कहा जाता है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के मुताबिक, प्रदेश में इनकी आबादी करीब एक करोड़ है, जो कुल जनसंख्या का तीन से चार फीसदी बैठती है। आंकड़ों से ज्यादा अहम उनकी राजनीतिक भूमिका है। प्रदेश के 37 जिलों की 67 विधानसभा सीटों पर कायस्थों की अच्छी-खासी मौजूदगी है और करीब 25 सीटों पर वे निर्णायक स्थिति में माने जाते हैं।यूपी और बिहार में श्रीवास्तव, सिन्हा, माथुर, सक्सेना जैसे उपनामों से पहचाने जाने वाले कायस्थ खुद को भगवान चित्रगुप्त का वंशज मानते हैं। व्यापार, शिक्षा, प्रशासन और राजनीति, हर क्षेत्र में उनकी मौजूदगी रही है। कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, आगरा, बरेली, अलीगढ़ जैसे शहरों में उनकी संख्या और प्रभाव दोनों ही मजबूत हैं।

बिहार में कम संख्या, लेकिन बड़ा संदेश

बिहार में कायस्थों की आबादी महज 0.5 फीसदी के आसपास मानी जाती है। इसके बावजूद राजनीति में उनका असर अक्सर संख्या से ज्यादा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने सिर्फ एक-एक सीट पर ही कायस्थ उम्मीदवार उतारे थे। बीजेपी की ओर से नितिन नबीन ही अकेले कायस्थ प्रत्याशी थे, जो लगातार पांचवीं बार चुनाव जीतकर मंत्री भी बने।नितिन नबीन के पिता नवीन किशोर सिन्हा भी बीजेपी के बड़े नेताओं में गिने जाते थे। नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने न सिर्फ एक अनुभवी संगठनकर्ता को आगे किया है, बल्कि एक ऐसे समुदाय को भी संदेश दिया है, जो खुद को अक्सर हाशिये पर महसूस करता रहा है।

आगे क्या संकेत दे रही है बीजेपी

माना जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद, 14 जनवरी के आसपास नितिन नबीन को पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी मिल सकती है। इससे पहले अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद जेपी नड्डा भी कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर ही पार्टी की कमान संभाल चुके हैं।बिहार में ही रविशंकर प्रसाद, ऋतुराज सिन्हा और संजय मयूख जैसे नेता भी कायस्थ समुदाय से आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे शीर्ष नेताओं की ओर से नितिन नबीन को बधाइयां मिलना यह दिखाता है कि पार्टी नेतृत्व इस फैसले को कितनी गंभीरता से देख रहा है।कुल मिलाकर, नितिन नबीन की नियुक्ति सिर्फ एक संगठनात्मक बदलाव नहीं है। यह बीजेपी की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसमें वह सामाजिक संतुलन, पुराने प्रभावशाली समुदायों और नए राजनीतिक संदेशों को एक साथ साधने की कोशिश कर रही है। आने वाले चुनावी दौर में यह फैसला कितना असर दिखाता है, यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी ने कायस्थ कार्ड खेलकर सियासी बहस जरूर तेज कर दी है।

राष्ट्रीय हिंदी साप्ताहिक

भारत श्री

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम

सोमवार, 15 दिसंबर 2025, विक्रम संवत 2080

हिंसा के पीछे की विचारधारा

ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर जो अंधाधुंध गोली चलाकर 15 लोगों की हत्या की गई और अनेक लोग घायल हो गए इस गोली चालन में भी दो मुसलमान बाप बेटों का ही हाथ बताया जा रहा है। आमतौर पर दुनिया में इस तरह के अंधाधुंध हत्याओं में मुसलमान का ही हाथ पाया जाता है इसलिए दुनिया के मुसलमान को इस बात पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि उन्हें इस तरह की शिक्षा कहां से प्राप्त हो रही है जिस शिक्षा के माध्यम से वे हिंसक हो जा रहे हैं। दुनिया की अन्य संस्कृतियों के लोग टारगेट को हिंसा करते हैं लेकिन मुसलमान सभी दूसरे धर्म के लोगों को अपना टारगेट मानता है किसी व्यक्ति को नहीं। यह कार्य भी कोई व्यवस्था नहीं करती बल्कि हर मुसलमान इस प्रकार दूसरे धर्म के लोगों को मारना अपना कर्तव्य समझता है। स्पष्ट है कि यह शिक्षा उन्हें धर्म गुरुओं से ही मिल रही है क्योंकि मुसलमान आमतौर पर नासमझ होता है वह अपने धर्म गुरुओं के इशारे पर चलता है और धर्मगुरु भी किसी किताब से ही संचालित होते हैं। हम इस प्रकार के हत्यारे को राज्य द्वारा दंड दिलवाएंगे यह बात सही है लेकिन हम सब लोगों का भी यह कर्तव्य है कि हम दो दिशाओं में सक्रिय हो। पहली हम मुसलमान से सतर्क रहे दूसरा कि हम मुसलमान को उस शिक्षा से दूर करें जहां से उन्हें इस तरह की गंदी शिक्षा प्राप्त होती है । हम समाज के लोग हैं हमारा कार्य अलग है सरकार का कार्य अलग है। सरकार अपना कार्य कर रही है हमें भी अपना कार्य करना चाहिए इस तरह की गंदी विचारधारा दुनिया में जीवित रहे यह हमारी असफलता है। लिए हम आप मिलकर इस विषय पर गंभीरता से विचार करें की दुनिया को ऐसी शिक्षा से कैसे मुक्त कराया जा सकता है।

बजरंग मुनि

UPPSC के बाहर उठा भरोसे का सवाल

@ **अनुराग पाठक**

प्रयागराज की सड़कों पर सोमवार को एक अलग ही बेचैनी दिखी। हाथों में फाइलें, आंखों में नाराज़गी और चेहरों पर अपने भविष्य की चिंता लिए सैकड़ों छात्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी UPPSC के मुख्यालय के बाहर इकट्ठा हो गए। ये वही छात्र हैं, जो PCS, RO-ARO जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं की तैयारी में अपने जीवन के कई साल लगा चुके हैं। उनका कहना है कि मेहनत उन्होंने की, परीक्षा उन्होंने दी, लेकिन अब नतीजों की प्रक्रिया इतनी धुंधली हो गई है कि भरोसा डगमगाने लगा है।यह प्रदर्शन अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे महीनों से सुलग रहा असंतोष था, जो सोमवार को खुलकर सामने आ गया। छात्रों का आरोप है कि आयोग परीक्षाओं में पारदर्शिता नहीं बरत रहा और जरूरी जानकारियां छुपाई जा रही हैं। यही वजह है कि PCS-2024 प्रीलिम्स और RO-ARO-2023 प्रीलिम्स से जुड़े अभ्यर्थी बड़ी संख्या में सड़क पर उतर आए।

सुबह से ही प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में हलचल बढ़ने लगी थी। UPPSC मुख्यालय के बाहर छात्र जुटने लगे। देखते ही देखते संख्या सैकड़ों में पहुंच गई। नारे लगे, पोस्टर उठे और आयोग से जवाब मांगा जाने लगा। हालात को देखते हुए पुलिस प्रशासन को भारी बल तैनात करना पड़ा। RAF और अन्य अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी ने माहौल की गंभीरता को साफ दिखा दिया।छात्रों की सबसे बड़ी नाराज़गी संशोधित उत्तर कुंजी को लेकर है। उनका कहना है कि फाइनल रिजल्ट घोषित हो चुका है, लेकिन अब तक रिवाइज्ड आंसर की सार्वजनिक नहीं की गई। अभ्यर्थियों के मुताबिक, यह जानना उनका अधिकार है कि अंतिम रूप से किन उत्तरों को सही माना गया। बिना आंसर की जारी किए परिणाम घोषित करना संदेह को जन्म देता है।

इतना ही नहीं, कट ऑफ मार्क्स को लेकर भी छात्रों में भारी असंतोष है। अलग-अलग कैटेगरी के कट ऑफ अंक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। इससे न सिर्फ चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बल्कि उन अभ्यर्थियों के मन में भी भ्रम है, जो कुछ अंकों से पीछे रह गए। छात्रों का कहना है कि जब कट ऑफ और अंक ही नहीं बताए जाएंगे, तो कोई यह कैसे समझेगा कि वह कहां चूक गया।प्रदर्शन कर रहे एक अभ्यर्थी ने कहा कि आयोग पारदर्शिता की बात तो करता है, लेकिन व्यवहार में उसका पालन नहीं दिखता। अगर सब कुछ सही है, तो आंसर की, कट ऑफ और मार्क्स लिस्ट छुपाने की जरूरत क्यों है। उनका कहना था कि वर्षों की मेहनत के बाद अगर प्रक्रिया पर ही भरोसा न रहे, तो यह सबसे बड़ा अन्याय है।छात्रों की मांगें यहीं खत्म नहीं होतीं। उन्होंने एक लिखित मांग पत्र के जरिए अपनी समस्याएं सामने रखीं। सबसे पहली मांग यही है कि संशोधित फाइनल आंसर की तुरंत जारी की जाए। इसके साथ ही सभी कैटेगरी के कट ऑफ मार्क्स सार्वजनिक किए जाएं। इसके अलावा, सभी अभ्यर्थियों की मार्क्स लिस्ट भी आयोग की वेबसाइट पर डाली जाए, ताकि हर कोई अपनी स्थिति साफ तौर पर देख सके।OMR शीट को लेकर भी छात्रों में गहरी नाराज़गी है। उनका कहना है कि परीक्षा में भरी गई OMR शीट की कार्बन कॉपी या स्कैन कॉपी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इससे अभ्यर्थी खुद देख सकेगा कि उसने क्या भरा था और जांच में कहां गलती हुई। कई छात्रों का आरोप है कि OMR मूल्यांकन में गड़बड़ी की आशंका बनी रहती है, जिसे पारदर्शिता से ही दूर किया जा सकता है।

कई अभ्यर्थियों ने बताया कि वे उम्र की सीमा के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। हर देरी उनके लिए एक नया तनाव लेकर आती है। नौकरी, शादी, परिवार, सब कुछ इसी एक परीक्षा पर टिका होता है। जब प्रक्रिया ही भरोसेमंद न लगे, तो मानसिक दबाव और बढ़ जाता है।मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि उत्तर पुस्तिकाएं सार्वजनिक नहीं की जातीं और न ही पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया स्पष्ट है। इससे यह शक गहराता है कि मूल्यांकन निष्पक्ष हुआ या नहीं। कई छात्र कहते हैं कि वे अपने उत्तरों को देखना चाहते हैं, ताकि अगली बार बेहतर तैयारी कर सकें, लेकिन यह मौका उन्हें नहीं मिलता।प्रयागराज लंबे समय से प्रतियोगी छात्रों का केंद्र रहा है। यहां की गलियों में सपने पलते हैं, किताबों की दुकानें उम्मीद बेचती हैं और चाय की दुकानों पर भविष्य की योजनाएं बनती हैं। सोमवार का प्रदर्शन उसी टूटते भरोसे की आवाज था, जो इन गलियों से उठी और आयोग के दरवाजे तक पहुंची।अब निगाहें आयोग पर टिकी हैं। सवाल सिर्फ आंसर की या कट ऑफ का नहीं है। सवाल उस भरोसे का है, जो लाखों युवाओं ने सिस्टम पर किया है। अगर पारदर्शिता लौटती है, तो शायद यह गुस्सा थमे। अगर नहीं, तो यह आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप ले सकता है।

जुबानी तीर

UPPSC की परीक्षाओं को लेकर जिस तरह छात्र सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं, वह सरकार की बड़ी नाकामी है। कट-ऑफ, आंसर-की और अंक छुपाना पारदर्शिता नहीं, बल्कि संदेह को जन्म देता है। मेहनत करने वाले युवाओं को शक की निगाह से नहीं, भरोसे के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए।

अखिलेश यादव (समाजवादी पार्टी अध्यक्ष)

UPPSC से जुड़े अभ्यर्थियों की मांगें पूरी तरह जायज हैं। भर्ती प्रक्रिया में साफ-सफाई और समयबद्धता न होने से छात्र मानसिक तनाव में हैं। आयोग को चाहिए कि बिना देरी के सभी जरूरी जानकारियां सार्वजनिक करे, ताकि युवाओं का विश्वास बना रहे।

मायावती (बसपा सुप्रीमो)

जब छात्र अपने हक की जानकारी मांगने के लिए सड़कों पर उतरते हैं, तो इसका मतलब है कि व्यवस्था ने उन्हें सुना नहीं। उत्तर प्रदेश के युवाओं को पारदर्शी परीक्षा प्रणाली और जवाबदेह संस्थान चाहिए। सरकार को टालने के बजाय समाधान की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए।

प्रियंका गांधी वाड्रा (कांग्रेस महासचिव)

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक डॉ. महिमा मक्कर द्वारा एच0टी0 मीडिया, प्लॉट नं. 8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा-9 उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं जी. एफ. 5/115, गली नं. 5 संत निरंकारी कालोनी, दिल्ली-110009 से प्रकाशित । संपादकः महिमा मक्कर, RNI No. DELHI/2019/77252, संपर्क 011-43563154

विज्ञापन एवं वार्षिक सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफिस के पते पर सम्पर्क करें या फिर इन नम्बरों - 9667793987 या 9667793985 पर बात करें या इस पर media@bharatshri.com ईमेल करें।

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

ठंड में बालों की सेहत का आयुर्वेदिक रास्ता

प्राकृतिक देखभाल से मजबूत और चमकदार बाल

सर्दियों का मौसम जहां एक ओर सुकून और राहत लेकर आता है, वहीं दूसरी ओर यह त्वचा और बालों के लिए कई समस्याएं भी खड़ी कर देता है। ठंडी हवा, कम नमी, धूप की कमी और गरम पानी का अधिक इस्तेमाल बालों की प्राकृतिक नमी छीन लेता है। नतीजा यह होता है कि बाल रूखे, बेजान, टूटने वाले और झड़ने लगते हैं। कई लोगों को सर्दियों में डैंड्रफ, खुजली और दोमुंहे बालों की शिकायत भी बढ़ जाती है।आधुनिक समय में लोग इन समस्याओं से बचने के लिए केमिकल युक्त शैंपू और ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं, लेकिन आयुर्वेद बालों की देखभाल का एक ऐसा प्राकृतिक और स्थायी तरीका देता है, जो न केवल बालों की समस्याओं को दूर करता है, बल्कि जड़ से उन्हें मजबूत भी बनाता है। आयुर्वेद मानता है कि बालों की सेहत शरीर के अंदरूनी संतुलन से जुड़ी होती है। खासकर वात और कफ दोष का असंतुलन सर्दियों में बालों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है।

आयुर्वेद के अनुसार सर्दियों में बालों की समस्या क्यों बढ़ती है

आयुर्वेद में बालों को अस्थि धातु का उपधातु माना गया है। यानी जब शरीर में पोषण और नमी की कमी होती है, तो उसका असर सीधे बालों पर पड़ता है। सर्दियों में वात दोष बढ़ जाता है, जिससे शरीर में रूखापन आता है। यही रूखापन सिर की त्वचा को भी प्रभावित करता है और बाल कमजोर होने लगते हैं।इसके अलावा सर्दियों में लोग कम पानी पीते हैं, तली-भुनी चीजें ज्यादा खाते हैं और धूप कम लेते हैं। यह सभी कारण मिलकर बालों की जड़ों को कमजोर करते हैं। आयुर्वेद का समाधान बाहरी देखभाल के साथ-साथ अंदरूनी संतुलन पर भी जोर देता है।

सर्दियों में तेल मालिश का महत्व

आयुर्वेद में सिर पर नियमित तेल मालिश को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ठंड के मौसम में यह और भी जरूरी हो जाता है। तेल मालिश से सिर की त्वचा को पोषण मिलता है, रक्त संचार बढ़ता है और बालों की जड़ें मजबूत होती हैं।आयुर्वेद के अनुसार सर्दियों में तिल का तेल सबसे उत्तम माना जाता है। यह वात दोष को शांत करता है और सिर की त्वचा को गहराई से नमी देता है। इसके अलावा नारियल तेल में थोड़ा सा आंवला तेल मिलाकर लगाने से बालों का झड़ना कम होता है और बालों में प्राकृतिक चमक आती है।सप्ताह में कम से कम दो बार हल्के गुनगुने तेल से सिर की मालिश करनी चाहिए। मालिश के बाद तेल को कुछ समय तक लगा रहने दें, ताकि वह त्वचा में अच्छे से समा जाए।

आयुर्वेदिक उबटन और लेप

सर्दियों में केमिकल शैंपू का ज्यादा इस्तेमाल बालों को और रूखा बना सकता है। आयुर्वेद में प्राकृतिक उबटन और लेप का सुझाव दिया गया है, जो सिर की त्वचा को साफ करने के साथ-साथ पोषण भी देते हैं।रीठा, शिकाकाई और आंवला का चूर्ण बराबर मात्रा में मिलाकर हल्के गुनगुने पानी में भिगो दें। इस मिश्रण से बाल धोने पर न तो ज्यादा झाग बनेगा और न ही बालों की नमी खत्म होगी। यह मिश्रण डैंड्रफ को भी धीरे-धीरे कम करता है।इसके अलावा मेथी के दानों को रातभर भिगोकर पीस लें और उसमें थोड़ा दही मिलाकर सिर पर लगाएं। यह लेप सर्दियों में होने वाली खुजली और रूखेपन से राहत देता है।

आहार से भी जुड़ी है बालों की सेहत

आयुर्वेद साफ कहता है कि जैसा आहार होगा, वैसा ही शरीर और बाल होंगे। सर्दियों में अगर खानपान सही नहीं होगा, तो कोई भी बाहरी उपाय पूरी तरह असरदार नहीं होगा।इस मौसम में घी, तिल, मूंगफली, अखरोट और बादाम जैसे पौष्टिक और स्निग्ध पदार्थ खाने चाहिए। आंवला, गाजर और हरी सब्जियां बालों को अंदर से मजबूती देती हैं। आयुर्वेद में आंवला को बालों के लिए अमृत माना गया है। रोजाना आंवला मुरब्बा या आंवला चूर्ण का सेवन करने से बालों का झड़ना कम होता है और समय से पहले सफेद होने की समस्या भी घटती है।गुनगुना दूध और थोड़ी मात्रा में घी लेने से भी शरीर में नमी बनी रहती है, जिसका सीधा फायदा बालों को मिलता है।

पानी और दिनचर्या का असर

सर्दियों में लोग अक्सर प्यास कम लगने के कारण पानी कम पीते हैं, लेकिन यह बालों के लिए नुकसानदायक है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में जल तत्व का संतुलन जरूरी है। कम पानी पीने से सिर की त्वचा सूखने लगती है, जिससे डैंड्रफ और बाल झड़ने की समस्या बढ़ती है।इसके अलावा बहुत ज्यादा गरम पानी से सिर धोने से बचना चाहिए। गरम पानी बालों की जड़ों को कमजोर कर देता है। हल्के गुनगुने या सामान्य तापमान के पानी का इस्तेमाल बेहतर होता है।

तनाव और नींद का संबंध

आयुर्वेद बालों की समस्या को केवल बाहरी नहीं मानता, बल्कि मानसिक स्थिति से भी जोड़ता है। सर्दियों में धूप कम मिलने और दिन छोटे होने के कारण कई लोग तनाव और सुस्ती महसूस करते हैं। इसका असर बालों पर भी पड़ता है।रोजाना पर्याप्त नींद लेना और सुबह की हल्की धूप में कुछ समय बिताना बालों के लिए फायदेमंद होता है। आयुर्वेद में ब्रह्ममुहूर्त में उठना और नियमित दिनचर्या अपनाना बालों की सेहत के लिए जरूरी बताया गया है।

आयुर्वेदिक काढ़ा और घरेलू उपाय

सर्दियों में शरीर को अंदर से गर्म और संतुलित रखने के लिए आयुर्वेदिक काढ़े का सेवन भी लाभकारी होता है। अदरक, तुलसी और दालचीनी से बना हल्का काढ़ा रक्त संचार को बेहतर करता है, जिससे सिर तक पोषण सही तरीके से पहुंचता है।इसके अलावा रात में सोने से पहले पैरों के तलवों में थोड़ा सा तिल का तेल लगाना भी आयुर्वेद में बताया गया है। इसका अप्रत्यक्ष फायदा बालों की जड़ों को मिलता है और नींद भी बेहतर होती है।

प्राकृतिक देखभाल ही स्थायी समाधान

आयुर्वेद का मूल सिद्धांत यही है कि प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलना ही स्वास्थ्य का सबसे अच्छा तरीका है। सर्दियों में बालों की देखभाल के लिए ज्यादा प्रयोग करने के बजाय सरल और नियमित आयुर्वेदिक उपाय अपनाना ज्यादा असरदार होता है।अगर सही तेल, संतुलित आहार, पर्याप्त पानी और नियमित दिनचर्या को अपनाया जाए, तो सर्दियों में भी बाल मजबूत, घने और चमकदार बने रह सकते हैं।

आयुर्वेद न केवल बालों की मौजूदा समस्या को ठीक करता है, बल्कि भविष्य में होने वाली परेशानियों से भी बचाव करता है।ठंड के मौसम में बालों को संभालने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उन्हें प्रकृति के भरोसे सौंप दिया जाए, क्योंकि आयुर्वेद में हर समस्या का समाधान पहले से मौजूद है।

महात्मा रूपकला जी: सीताराम की मधुर लीला के रस भक्त

श्री अवध की पावन भूमि राम की लीला का आलोकित आंगन है। हर कण में दिव्यता की झलक बसती है, हर सांस में भगवती सरयू के तट की मधुरता घुली हुई सी लगती है। दशरथनंदन राम की कृपा से ही इस अवध क्षेत्र में बसने का सौभाग्य मिलता है। महात्मा रूपकला जी राम के परम कृपापात्र बने। उन्होंने सीताराम के चरण कमलों में शरण ली और उनकी मधुर रति के रस से असंख्य प्राणियों को तृप्त किया। यह उनके चरित्र का सबसे सरस स्वरूप था। विक्रम संवत् की बीसवीं शताब्दी में अवध क्षेत्र उनकी पवित्र उपस्थिति से वृंदावन सा हो गया। चरणों में पायल बांधे, हर श्वास के कंपन पर थिरकते हुए, मीता के कैंकर्य रस में डूबे हुए, राम के अनन्य उपासक रूपकला जी ने जो दिव्य यश पाया, वह रामभक्ति के इतिहास में प्रेमोपासना की एक अनमोल घटना है। उन्होंने विहार और अवध को ही नहीं, बल्कि समस्त रामभक्ति से विभूषित भूमि को अपनी सरस लीला-चरित्र का परिचय कराया। वे रसिक संत थे, प्रेमी महात्मा थे। गृहस्थाश्रम में गृहस्थ की तरह आचरण कर भगवान राम की कृपा पाई, और सन्यासाश्रम में राम की लीला माधुरी का अनुभव किया। भगवन्नाम कीर्तन और भगवत्प्रेम के प्रचार में ही अपना समय सार्थक किया। वे परम रामभक्त थे, जिनके जीवन का हर पल सीताराम की भक्ति से सराबोर था।

जन्म और बाल्यकाल की दिव्य लीला

महात्मा रूपकला जी का प्राकट्य विहार प्रांत के छपरा जनपद से सात मील दूर मुबारकपुर ग्राम में हुआ। उनके पितामह केवल कृष्ण जी अपने भाई से न पटने के कारण इलाहाबाद जनपद के आलमगंज उपनगर में रहने लगे थे। वे नीलकोठी में प्रमुख कार्यकर्ता के पद पर नियुक्त थे। उनके पुत्र तपस्वी राम, जो बड़े कोमल हृदय के भगवद्भक्त थे, रूपकला जी के पिता थे। रूपकला जी की माता का नाम शिवव्रती देवी था। रूपकला जी ने आलमगंज में सम्वत् 1897 वि. श्रावण कृष्ण नवमी को जन्म लिया। तपस्वी राम के ज्येष्ठ चाचा तुलसी राम बहुत बड़े भगवद्भक्त थे। उनकी देख-रेख में रूपकला जी का पालन-पोषण हुआ। बचपन का नाम भगवान प्रसाद था। जब वे छोटे-से बालक थे, तभी पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों को एकत्र कर उनमें शालिग्राम की भावना करते थे। बड़ी भक्ति और प्रेम से उनका पूजन किया करते थे। इस प्रकार भगवान की लीला में उनकी अनुरक्ति बचपन से ही बढ़ने लगी। साधु-संतों को देखकर बड़े आनंदित होते थे। माता-पिता के सात्विक जीवन का उनके चरित्र-विकास पर बड़ा प्रभाव पड़ा। भगवान राम के प्रेम में वे बाल्यावस्था से ही उन्मत्त रहते थे। बचपन के आठ साल आलमगंज में ही पूरे किए, और बड़े मनोयोग से शिक्षा प्राप्त की।

आठ साल की अवस्था में वे माता-पिता के साथ अपने पैतृक निवास मुबारकपुर आ गए। मुबारकपुर में दो सौ साल पहले एक सिद्ध फकीर मुबारक शाह रहते थे। उनकी उपस्थिति से आध्यात्मिक वातावरण बहुत अच्छा हो चुका था। इसी पुण्य भूमि में भगवान प्रसाद ने निवास कर भगवद्भक्ति कमाई। उनकी शिक्षा-दीक्षा का अच्छे से अच्छा प्रबंध कर दिया गया। धीरे-धीरे वे युवावस्था में प्रवेश करने लगे। मुबारकपुर में रामलीला का समारोह हुआ करता था। भगवान प्रसाद राम और सीता के स्वरूप के निकट खड़े होकर चंवर डुलाया करते थे। घटों युगल स्वरूप को मधुर और दिव्य झांकी से अपने नेत्र तृप्त किया करते थे। बचपन से ही भगवान के नाम में दृढ़ विश्वास रखते थे। एक बार शिक्षण-काल में वे नदी में स्नान करने गए। साथ में दो मित्र थे। स्नान करते समय उनके एक मित्र नंदकुमार बाबू गंगा में डूब गए। रूपकला जी भगवान के नाम का स्मरण करने लगे। वे प्रभु से प्रार्थना करने लगे कि हे देव, यदि नंदकुमार डूब जाएंगे तो मेरी हंसी नहीं होगी, आपके नाम की महिमा घट जाएगी। बड़ी देर में बड़े जोर से एक लहर उठी और नंदकुमार बाबू उनके पैरों के पास आ पड़े। इस प्रकार रूपकला जी के भगवद्विश्वास ने नंदकुमार के प्राण की रक्षा की। यह घटना उनके हृदय में भगवान के नाम की शक्ति को और गहरा जड़ें जमाने वाली थी, जहां हर संकट में राम का नाम ही सहारा बन जाता।

शिक्षा, गृहस्थ जीवन और प्रारंभिक कृपा कथाएं

उच्च कक्षा के अध्ययन काल में रूपकला जी ने 'तन-मन की स्वच्छता' नामक पुस्तक लिखी। इसे उन्होंने शिक्षा-निरीक्षक फैलेन महादेव के करकमलों में अर्पित कर दिया। फैलेन उनकी प्रतिभा से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें उप-शिक्षा-निरीक्षक के पद पर नियुक्त करा दिया। नौकरी पाने के पूर्व ही वे गृहस्थाश्रम स्वीकार कर चुके थे। छपरा जनपद के रेपुरा गांव के रहने वाले तथा कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्तार ठाकुर प्रसाद की सौभाग्यवती कन्या से उनका विवाह हो गया। वे ससुराल के निकट ही एक महात्मा कान्हर दास से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने कान्हर दास से गुरुमंत्र लेने की इच्छा प्रकट की, तो कान्हर दास ने संमत दिया कि अपने कुलगुरु महात्मा रामचरण दास से ही दीक्षा लेना उचित है। महात्मा रामचरण दास छपरा से थोड़ी दूर परसा नामक स्थान में रहते थे। वे अच्छे संत थे। भगवान प्रसाद को गुरुमंत्र प्रदान कर उन्होंने उनका नाम सीताराम शरण भगवान प्रसाद रखा। गुरु की कृपा से उनका भगवत्प्रेम बढ़ने लगा। थोड़े समय बाद पिता और पत्नी की मृत्यु से उनका वैराग्य भाव बढ़ गया। संसार की नश्वरता का ज्ञान हो गया, तथा सीताराम की अभय पद-प्राप्ति के लिए उनका मन समुत्सुक हो उठा। उनके नयनों में दशरथनंदन राम और जनकनंदिनी सीता की छवि आलोडित हो उठी। उन पर भगवती कृपा का अवतरण होने लगा।

एक बार ऋण देने के लिए उन्हें कुछ रुपयों की आवश्यकता थी। उन्होंने बड़ी चेष्टा की पर रुपयों का प्रबंध न हो सका। उनके मन में दृढ़ विश्वास था कि भगवान की कृपा से प्रबंध हो ही जाएगा। वे उन पर भरोसा कर बैठ गए। अचानक एक व्यक्ति आया, उसने सबके सामने उनके हाथ में एक लिफाफा रखकर कहा कि इसे अपने पास ही रखिए, मैं थोड़ी देर में आकर ले जाऊंगा। वह व्यक्ति फिर न दिखा पड़ता। रूपकला जी ने लिफाफा नहीं खोला। दो-तीन दिनों बाद उसमें उतने ही रुपये थे जितने ऋण में देने थे। एक पैसे की भी भूल नहीं थी। रूपकला जी ने इसे प्रभु की कृपा मानकर स्वीकार कर लिया और ऋण की भरपाई कर दी। उन्होंने सोचा कि गृहस्थाश्रम में रहने से प्रभु को मेरे लिए चिंता करनी पड़ती है। उन्होंने अयोध्या जाने का संकल्प किया। इसी बीच उनके जीवन पर एक अद्भुत घटना ने प्रभाव डाला। वे निरीक्षण कार्य के लिए विहट्टा रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूर एक दीहात में गए हुए थे। उन दिनों शिक्षा विभाग के सचिव क्राफ्ट महोदय कलकत्ता से पटना आए हुए थे और शीघ्र ही कलकत्ता जाने वाले थे। दीहात में ही सीताराम शरण भगवान प्रसाद को शिक्षा-निरीक्षक मार्टिन साहब का एक पत्र मिला, जिसमें पटना जाकर सचिव महोदय से किसी आवश्यक विषय पर संमत लेने का आदेश दिया गया था। वे विहट्टा स्टेशन पर आए, गाड़ी जा चुकी थी। इधर पटना स्टेशन पर गाड़ी आने का समय हो चुका था। क्राफ्ट महोदय इसी गाड़ी से कलकत्ता जाने वाले थे। भगवान प्रसाद को बड़ी चिंता हुई, वे विश्रामालय में बैठ गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने आवश्यक कागजों के साथ अपने आपको पटना स्टेशन के प्रतीक्षालय में पाया। सचिव से बात की तथा कलकत्ता के लिए गाड़ी छूटने पर वे प्रतीक्षालय में चले आए। आश्चर्य की बात तो यह हुई कि थोड़ी-सी झपकी आने के बाद उन्होंने अपने आपको विहट्टा स्टेशन के प्रतीक्षालय में पाया। प्रभु की लीला उनकी समझ में न आ सकी। उन्हें नौकरी का मोह तनिक भी न रहा। त्याग-पत्र देकर वे अवधवासी चले आए। जीविका-वृत्ति प्राप्त करने में एक साल लगा, पर उन्होंने पेंशन की चिंता नहीं की। अयोध्या आने के बाद सरकार ने उनकी पेंशन स्वीकृति दे दी। इस प्रकार गृहस्थाश्रम का परित्याग कर वे अपने आराध्य सीताराम के लीला क्षेत्र श्री अवध में आ गए। यहां आते ही उनके हृदय पर भगवान के प्रेम का मधुर रंग चढ़ गया। वे मंदिर-मंदिर घूम-घूमकर अपने प्रियतम का दर्शन कर निहाल होने लगे। साधु-संतों के समागम से भगवान की लीला-कथा का रसास्वादन करने लगे। उनके आगमन से अवध सरस हो उठा। सरयू की निर्मल धारा को दिव्यता और सरसता बढ़ गई। रामतरंग मणि तथा पंडित रामवल्लभाशरण आदि संतों से उनकी घनिष्ठता बढ़ने लगी। उनका जीवन सरस और पवित्र हो उठा।

गुरु दीक्षा और नामकरण की पावन कथा

'कांताभाव' की दीक्षा उन्होंने भागलपुर गुरहट्टा के महंत श्री हसकला जी से ली थी। रामानंदी सम्प्रदाय के दीक्षागुरु रामचरण दास जी थे। महाराज हसकला ने उन्हें रूपकला नाम प्रदान किया था। एक बार अयोध्या निवास काल में वे रात को सोते हुए उठ बैठे। लोगों ने कारण पूछा तो कहा कि गुरुदेव का विमान जा रहा है, विदा लेने आए हुए थे। दूसरे दिन तार द्वारा पता लगा कि ठीक उसी समय हसकला जी महाराज ने साकेत लोक के लिए महाप्रस्थान किया था। यह घटना रूपकला जी की अनन्य गुरुभक्ति को द्योतक है। गुरु की कृपा से उनका हृदय सीताराम के प्रेम से परिपूर्ण हो गया, जैसे कोई कमल सरयू के जल में खिल उठे।

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

चीन का 1 ट्रिलियन डॉलर का ऐतिहासिक व्यापार अधिशेष: पीछे का राज़, भारत और दुनिया पर असर

आंकड़ों की चौंकाने वाली कहानी

चीन ने 2025 के पहले 11 महीनों में अपना व्यापार अधिशेष पहली बार 1 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर पहुंचा लिया है, जो कुल 1.08 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा है। यह पिछले साल के रिकॉर्ड 993 बिलियन डॉलर को पीछे छोड़ गया। नवंबर में ही अधिशेष 111.68 बिलियन डॉलर का रहा, जो तीसरा सबसे बड़ा मासिक आंकड़ा है। निर्यात में 5.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जो उम्मीद से ज्यादा थी, जबकि आयात सिर्फ 1.9 प्रतिशत बढ़ा, जो घरेलू मांग की कमजोरी दिखाता है। अमेरिका के साथ व्यापार गिरा है—निर्यात 29 प्रतिशत कम हो गया, लेकिन यूरोप को 14.8 प्रतिशत, ऑस्ट्रेलिया को 35.8 प्रतिशत और दक्षिण-पूर्व एशिया को 8.2 प्रतिशत ज्यादा सामान बेचा गया। इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में तेजी आई, क्योंकि दुनिया भर में इनकी कमी थी। यह अधिशेष चीन की मैन्युफैक्चरिंग ताकत को दिखाता है, लेकिन साथ ही यह सवाल उठाता है कि क्या यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है या खतरा। भारत के संदर्भ में देखें तो चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा अप्रैल-अक्टूबर 2025 में 64 बिलियन डॉलर पहुंच गया, जो पूरे वित्तीय साल 2025 में 99 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो सकता है। चीन का भारत के साथ अधिशेष अगस्त तक 77.7 बिलियन डॉलर था, जो 16 प्रतिशत बढ़ा। वैश्विक स्तर पर यह आंकड़ा चिंता पैदा कर रहा है, क्योंकि यह असंतुलन को बढ़ावा देता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने कहा है कि चीन को निर्यात पर निर्भरता कम कर घरेलू खपत बढ़ानी चाहिए, वरना वैश्विक विकास प्रभावित होगा।

अधिशेष के पीछे छिपे कारण: निर्यात की ताकत और घरेलू कमजोरी का मेल

चीन के इस विशाल अधिशेष के पीछे कई कारण हैं, जिनमें निर्यात की मजबूत छवि और घरेलू बाजार की कमजोरी दोनों शामिल हैं। सबसे बड़ा कारण कमजोर युआन है, जो चीनी सामान को दुनिया भर में सस्ता बनाता है—पिछले कुछ सालों में यह कई मुद्राओं के मुकाबले कमजोर रहा। हाई-टेक निर्यात में उछाल आया, जैसे इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी), सेमीकंडक्टर (24.7 प्रतिशत बढ़े) और जहाज निर्माण (26.8 प्रतिशत बढ़ा)। चीन ने जापान को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक बन गया, 2025 में 6 मिलियन से ज्यादा कारें बेचीं। अमेरिकी टैरिफ (औसत 47.5 प्रतिशत) के कारण निर्यात अमेरिका से घटा, लेकिन यूरोपीय संघ को 8.1 प्रतिशत, एशियन देशों और ग्लोबल साउथ को ज्यादा बेचा गया। आयात में गिरावट आई—पहले 11 महीनों में -0.6 प्रतिशत—क्योंकि प्रॉपर्टी संकट से स्टील और लकड़ी जैसे आयात कम हुए, और घरेलू उत्पाद विदेशी को पीछे धकेल रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग की ताकत ने 66 में से 74 तकनीकों में चीन को लीडर बना दिया, जहां वह पश्चिमी प्रतिस्पर्धियों से सस्ता सामान देता है। लेकिन यह अधिशेष घरेलू मांग की कमजोरी को छिपाता है—उपभोक्ता खर्च कम है, प्रॉपर्टी बाजार सुस्त है। वैश्विक कमी की वजह से चीनी निर्यात बढ़े, लेकिन आईएमएफ चेतावनी देता है कि यह मॉडल टिकाऊ नहीं। भारत के लिए यह सस्ते चीनी सामान का बाढ़ लाता है, जो स्टील और केमिकल्स जैसे क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाता है। कुल मिलाकर, ये कारण दिखाते हैं कि अधिशेष सिर्फ सफलता नहीं, बल्कि आर्थिक असंतुलन का संकेत है—चीन को घरेलू सुधारों पर ध्यान देना होगा ताकि वैश्विक व्यापार निष्पक्ष बने।

भारत पर असर: व्यापार घाटा बढ़ा, नई चुनौतियां खड़ी

चीन के 1 ट्रिलियन डॉलर के अधिशेष का भारत पर सीधा असर पड़ रहा है, जहां व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है और घरेलू उद्योगों पर दबाव बन रहा है। अप्रैल से अक्टूबर 2025 तक भारत का चीन के साथ घाटा 64 बिलियन डॉलर हो गया, जो पिछले साल से 16 प्रतिशत ज्यादा है। पूरे साल 2025 में यह 99 बिलियन डॉलर से ऊपर जा सकता है, क्योंकि चीन भारत को सस्ते सामान बेच रहा है जबकि हमारा निर्यात सीमित है। स्टील, रबर, केमिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में चीनी आयात का बोलबाला है, जो भारतीय मैन्युफैक्चरिंग को नुकसान पहुंचा रहा। सरकार ने एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाई है ताकि सस्ते आयात से बचा जा सके, लेकिन यह पर्याप्त नहीं लगता। रणनीतिक रूप से, यह घाटा भारत की 'मेक इन इंडिया' को कमजोर करता है, क्योंकि चीनी कंपनियां वैश्विक बाजार में सस्ते दामों से आगे निकल रही हैं। हालांकि, कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं—भारत रूस और अन्य देशों से व्यापार बढ़ा रहा है, जो विविधता ला सकता है। लेकिन कुल मिलाकर, यह अधिशेष भारत को मजबूर करता है कि वह अपनी नीतियां तेजी से बदले, जैसे आयात शुल्क बढ़ाना या घरेलू उत्पादन को सब्सिडी देना।

दुनिया पर प्रभाव: असंतुलन की चिंता, लेकिन विकास में बड़ा योगदान

चीन का यह रिकॉर्ड अधिशेष वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए दोहरी तलवार है—एक तरफ 40 प्रतिशत वैश्विक विकास में योगदान, दूसरी तरफ असंतुलन की बढ़ती चिंता। यूरोप और अमेरिका में चीनी निर्यात की बाढ़ से बाजार सस्ते सामान से भर गए, जिससे स्थानीय उद्योग दबाव में हैं। यूरोपीय संघ ने चीनी ईवी पर टैरिफ लगाए, क्योंकि निर्यात 8.1 प्रतिशत बढ़ा। अमेरिकी टैरिफ के बावजूद चीन ने रास्ता बदल लिया, जिससे वैश्विक बाजार हिस्सा 15 प्रतिशत से 16.5 प्रतिशत तक पहुंच सकता है 2030 तक। आईएमएफ ने चेताया कि यह मॉडल 'बहुत बड़ा' है निर्यात पर निर्भर रहने के लिए, और घरेलू खपत बढ़ानी चाहिए वरना संकट गहरा सकता है। लेकिन सकारात्मक रूप से, चीन की मैन्युफैक्चरिंग ने वैश्विक कमी पूरी की, जैसे सेमीकंडक्टर और जहाज। विकासशील देशों को सस्ते सामान मिले, लेकिन विकसित देशों में संरक्षणवाद बढ़ रहा—टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाएं। चैथम हाउस के अनुसार, युआन की सराहना से आयात बढ़े और प्रतिस्पर्धा निष्पक्ष बनेगी। भारत जैसे देशों के लिए यह दबाव है, लेकिन वैश्विक विकास में चीन का रोल अहम है।

आगे की राह: संतुलन कैसे लाएं, वैश्विक सहयोग की जरूरत

चीन के अधिशेष से निकलने वाली राह में संतुलन मुख्य है—निर्यात पर निर्भरता कम कर घरेलू सुधारों पर जोर। विशेषज्ञ सुझाते हैं कि युआन को धीरे-धीरे मजबूत किया जाए, ताकि आयात बढ़े और अधिशेष घटे। प्रॉपर्टी संकट सुलझाना और उपभोक्ता खर्च बढ़ाना जरूरी है, वरना वैश्विक टैरिफ युद्ध तेज होगा। भारत को अपनी नीतियां मजबूत करनी होंगी, जैसे निर्यात प्रोत्साहन और एंटी-डंपिंग को सख्त बनाना। वैश्विक स्तर पर, सहयोग से निष्पक्ष व्यापार संभव है—डब्ल्यूटीओ जैसे मंचों पर बातचीत। यह अधिशेष दिखाता है कि चीन की ताकत दुनिया को फायदा पहुंचा सकती है, लेकिन बिना संतुलन के खतरा है। क्या आने वाले सालों में बदलाव आएगा? यह समय बताएगा, लेकिन सबको मिलकर काम करना होगा ताकि व्यापार सभी के लिए फायदेमंद बने।

आदिकाल से है सनातन धर्म

आदिकाल का अर्थ है कि जब भी पृथ्वी, जल, पहाड़, मनुष्य तथा जीव भी इतनी ही संख्या में थे जितने कि आज हैं। उस समय मैं था और आप सब भी थे, लेकिन आपको याद नहीं है मुझे याद है। अभी तक कुछ घटा या बढ़ा नहीं है। उस समय कोई धर्म नहीं था, केवल सनातन धर्म था।

@ भारतश्री व्यूरो

यूं तो पूरे विश्व में 4200 धर्म कहे जाते हैं लेकिन सनातन धर्म ही ऐसा प्रारूप है जिसके माध्यम से परमात्मा को पाया जा सकता है। यह आदिकाल से है। आदिकाल का अर्थ है कि जब भी पृथ्वी, जल, पहाड़, मनुष्य तथा जीव भी इतनी ही संख्या में थे जितने कि आज हैं। उस समय मैं था और आप सब भी थे, लेकिन आपको याद नहीं है मुझे याद है। अभी तक कुछ घटा या बढ़ा नहीं है। उस समय कोई धर्म नहीं था, केवल सनातन धर्म था। उस समय हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ नहीं था, यह अभी कुछ सालों से प्रकाश में आए हैं इसके बाद पंजाब में रहने वाला पंजाबी, हरियाणा में रहने वाला हरियाणवी, सिंध में रहने वाला सिंधी कहा जाने लगा। इस्लाम धर्म में कहा जाता है कि कयामत आने तक मुर्दों को कब्र में सोना पड़ेगा। कयामत वाले दिन ही सभी का न्याय होगा कि किसे जन्नत मिलेगी और किसे दोजख। सनातन धर्म में इसी जन्म में इसी योनि में पाठ के द्वारा मुक्ति और परमात्मा की प्राप्ति संभव है। मैं जब मुस्लिम देशों में गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जिस तरह की बात करते हो, उसके बदले में हम तुम्हें मार देंगे क्योंकि तुम वह बोलते हो जो हमारी कुरान में नहीं है। मैंने उनसे कहा कि यदि मैं वह बोलूंगा जो कुरान में है, उस सत्य को जानकर तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मैंने मुक्ति को जान लिया

है, मैं जहां जाऊंगा उसका मुझे मालूम है।
मां दुर्गा करती है मनुष्य के शरीर की रक्षा

भगवती मां दुर्गा मनुष्य के शरीर के अंगों की रक्षा विभिन्न रूपों में करती हैं। मां दुर्गा के नौ रूप हैं जिन्हें 'नवदुर्गा' कहते हैं। उनके पृथक-पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है। दूसरी का नाम ब्रह्मचारिणी है। तीसरा स्वरूप चन्द्रघण्टा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी को कूष्माण्डा कहते हैं। पांचवीं दुर्गा का नाम स्कन्दमाता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है।

ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं यही रूप मां दुर्गा है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में आ गया हो। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता, उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरि! जो आपका चिन्तन करते हैं, उनकी आप निःसंदेह रक्षा करती हो।

मां के विभिन्न स्वरूपों के वाहन

चामुण्डा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं। वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं। ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड पर ही आसन जमाती हैं। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान हैं और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योगशक्तियों से सम्पन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं।

ये सम्पूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुन्त और त्रिशूल एवं उत्तम शांगधनुष आदि अस्त्र-शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना-यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है।

रक्षा के लिए मां से करें प्रार्थना

मां भगवती से अपनी रक्षा करने के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। शत्रुओं का भय नष्ट करने वाली जगदम्बिके! मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्यकोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली मृगवाहिनी देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करें। ब्रह्माणि! आप ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुण्डा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें।

वामभाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधरी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करें। भौंहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघण्टा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्यभाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शाकंभरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगन्धा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करें, नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चण्डिका कण्ठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघण्टा गले की घंटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ठोढ़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी मेरुदंड में रहकर रक्षा करें।

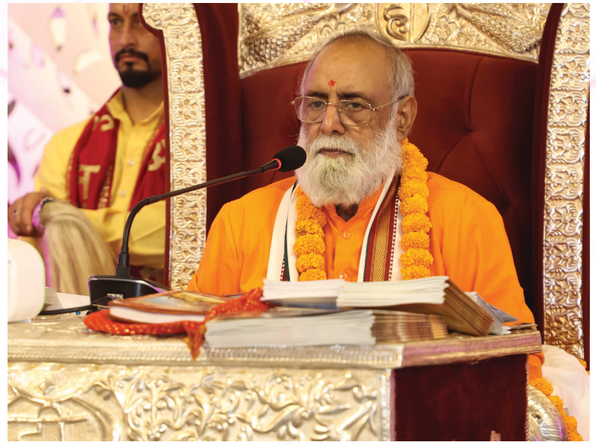

यौन व्यापार पर नई बहस: फ्रांस-इटली में पाबंदी ढील देने की हवा, EU ने क्यों खींची थी लगाम?

फ्रांस और इटली में क्या चल रहा है?

यूरोप के दो बड़े देश फ्रांस और इटली में यौन व्यापार को लेकर नई हलचल मची हुई है। दिसंबर 2025 में फ्रांस की दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली ने ब्रोथल्स यानी वेश्यालयों को फिर से खोलने का प्रस्ताव पेश करने की तैयारी कर ली है। ये ब्रोथल्स सेक्स वर्कर्स के सहकारी समूहों के तहत चलेंगे, जहां महिलाएं खुद मालिक होंगी। पार्टी का कहना है कि इससे सेक्स वर्कर्स की सुरक्षा बढ़ेगी और उन्हें सोशल सिक्योरिटी जैसे फायदे मिलेंगे। दूसरी तरफ, अप्रैल 2025 में इटली ने सेक्स वर्क को आधिकारिक बिजनेस कोड दे दिया है। ये ATECO कोड टैक्स और डेटा कलेक्शन के लिए है, जिससे सेक्स वर्कर्स अब वैट नंबर ले सकती हैं और अपनी कमाई को वैध तरीके से दिखा सकती हैं। पहले वो अक्सर 'मसाज' जैसी कोटियों का सहारा लेती थीं। ये बदलाव EU के नए अकाउंटिंग नियमों से प्रेरित हैं, लेकिन इटली में अभी भी ब्रोथल चलाना गैरकानूनी है। इन कदमों से सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सेक्स वर्क को सामान्य काम की तरह मानने की दिशा में कदम हैं? फ्रांस में 2016 का कानून खरीदारों को सजा देता है, जबकि बेचने वाली को अपराधी नहीं मानता। इटली में 1958 के मर्लिन कानून ने पिंपिंग और ब्रोथल्स पर रोक लगाई, लेकिन बेचना-खरीदना वैध है। अब ये प्रस्ताव पुरानी बहस को हवा दे रहे हैं। सेक्स वर्कर्स के ग्रुप्स का कहना है कि इससे उनकी जिंदगी आसान हो सकती है, लेकिन आलोचक चेतावनी दे रहे हैं कि ये शोषण को बढ़ावा दे सकता है। EU में 27 देशों के अलग-अलग कानूनों के बीच ये बदलाव व्यापक चर्चा छेड़ रहे हैं। क्या ये महिलाओं की आजादी का प्रतीक बनेगा या नई मुश्किलें खड़ी करेगा? ये सवाल समाज को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। कुल मिलाकर, ये कदम सेक्स इंडस्ट्री को छाया से बाहर लाने की कोशिश लगते हैं, लेकिन रास्ता लंबा है।

EU में सख्ती की जड़ें: ट्रैफिकिंग और महिलाओं की सुरक्षा क्यों बनी प्राथमिकता?

EU के कई देशों ने यौन व्यापार पर सख्त लगाम कसी क्योंकि ये मानव तस्करी और शोषण से जुड़ा था। 1990 के दशक से EU ने इसे लिंग असमानता और हिंसा के रूप में देखा। स्वीडन ने 1999 में नॉर्डिक मॉडल अपनाया, जहां खरीदार को अपराधी माना जाता है, लेकिन बेचने वाली को पीड़ित। ये मॉडल ट्रैफिकिंग रोकने के लिए था, क्योंकि ज्यादातर सेक्स वर्कर्स विदेशी महिलाएं होती हैं जो जबरदस्ती लाई जाती हैं। EU की 2011/36 डायरेक्टिव ने सदस्य देशों को ट्रैफिकिंग के खिलाफ एकजुट किया। फ्रांस ने 2016 में ये मॉडल अपनाया, खरीदारों पर 1500 यूरो तक जुर्माना लगाया, ताकि डिमांड कम हो। इटली का 1958 का कानून ब्रोथल्स बंद करने पर केंद्रित था, क्योंकि WWII के बाद नैतिक सफाई अभियान चला। EU पार्लियामेंट की 2014 और 2023 की रिपोर्ट्स कहती हैं कि नॉर्डिक मॉडल ने स्ट्रीट प्रॉस्टिट्यूशन को 50% तक कम किया। लेकिन आलोचक कहते हैं कि ये सेक्स वर्कर्स को और छिपा देता है। जर्मनी और नीदरलैंड्स जैसे देशों ने रेगुलेशन चुना, जहां हेल्थ चेक और लाइसेंस हैं। EU में 10% GDP छाया अर्थव्यवस्था से आता है, जिसमें सेक्स वर्क बड़ा हिस्सा है। ट्रैफिकिंग के आंकड़े डराने वाले हैं: 2022 में EU में 70% ट्रैफिकिंग पीड़ित महिलाएं थीं, ज्यादातर सेक्स के लिए। देशों ने ये पाबंदियां लगाईं ताकि महिलाओं को बाहर निकाल सकें, एजुकेशन और जॉब्स दें। लेकिन अब बहस ये है कि सख्ती ने क्या हल किया? सेक्स वर्कर्स कहती हैं कि ये उन्हें अपराधी बना देता है। EU का लक्ष्य था शोषण खत्म करना, लेकिन अब बदलाव की मांग बढ़ रही है। क्या पुरानी चिंताएं आज भी वैध हैं, या समय के साथ नजरिया बदलना चाहिए? ये सवाल नीति-निर्माताओं को परेशान कर रहे हैं।

फ्रांस का साहसिक कदम: ब्रोथल्स फिर से खुलें, लेकिन महिलाओं के कंट्रोल में

फ्रांस में नेशनल रैली पार्टी का ब्रोथल्स खोलने का प्रस्ताव बहस का केंद्र बन गया है। सांसद जीन-फिलिप टैंगुई कहते हैं कि 1946 के बाद बंद ये जगहें अब सहकारी रूप में लौटें, जहां सेक्स वर्कर्स खुद बॉस हों। पार्टी चीफ मरीन ले पेन का समर्थन है, और बिल जल्द संसद में आएगा। वजह? 2016 का कानून, जो खरीदारों को सजा देता है, ने सेक्स वर्कर्स की हालत बिगाड़ दी। वो अब सड़कों पर ज्यादा असुरक्षित हैं, और सोशल बेनिफिट्स से वंचित। प्रस्ताव कहता है कि सहकारी से वो टैक्स देंगी, पेंशन और बेरोजगारी भत्ता पाएंगी। इतिहास में फ्रांस के ब्रोथल्स मशहूर थे- ला चबाने जैसे लग्जरी स्पॉट जहां सेलिब्रिटी आते थे। लेकिन 1946 के मार्थ रिचर्ड कानून ने नैतिक आधार पर इन्हें बंद कर दिया। अब RN का तर्क है कि ये महिलाओं को 'अपना साम्राज्य' देगा। लेकिन प्रतिक्रियाएं तीखी हैं। सेक्स वर्कर्स ग्रुप STRASS ने इसे प्रचार स्टंट कहा, क्योंकि RN विदेशी महिलाओं को रोकना चाहती है। एंटी-प्रॉस्टिट्यूशन ग्रुप मूवमेंट डू निड ने इसे 'बेतुका' बताया, कहा ब्रोथल्स सुरक्षा नहीं देते। इक्वालिटी मिनिस्टर ऑरॉर बर्जे ने कहा, 'इच्छा को नहीं खरीदा जा सकता, ये पुरुष वर्चस्व है।' कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टियां इसे 'सेक्शुअल पॉपुलिज्म' बता रही हैं। कुछ RN सदस्य खुद हैरान हैं। 2024 में गैब्रियल अटाल सरकार ने प्रॉस्टिट्यूशन के खिलाफ नेशनल स्ट्रैटेजी लॉन्च की, मसाज पार्लर्स पर नजर। लेकिन ये प्रस्ताव 2027 चुनावों से पहले RN की स्ट्रैटेजी लगता है। क्या ये पास होगा? मुश्किल, लेकिन बहस जरूर छेड़ेगा। सेक्स वर्कर्स को अधिकार चाहिए, लेकिन शोषण का डर भी। फ्रांस समाज को ये सोचने को मजबूर कर रहा है कि सुरक्षा और आजादी का बैलेंस कैसे बने।

इटली की चुपचाप क्रांति: ATECO कोड से सेक्स वर्क पर नई रोशनी

इटली में अप्रैल 2025 का ATECO कोड अपडेट सेक्स वर्कर्स के लिए बड़ा बदलाव लाया। नेशनल स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट ISTAT ने इसे पर्सनल सर्विसेज कैटेगरी में डाला, टैटू स्टूडियो और पार्टी ऑर्गेनाइजर्स के साथ। अब सेक्स वर्कर्स वैट नंबर ले सकती हैं, टैक्स भर सकती हैं और कमाई वैध दिखा सकती हैं। EU के नए अकाउंटिंग नियमों से ये आया, जो अवैध गतिविधियों का जिक्र करते हैं। लेकिन ISTAT ने साफ कहा कि सिर्फ वैध काम ही गिनेगा। इटली में प्रॉस्टिट्यूशन लीगल है, लेकिन ब्रोथल्स और पिंपिंग पर 1958 के मर्लिन कानून से रोक। इंडस्ट्री छाया में थी, 2022 में 220 बिलियन डॉलर की वैल्यू, GDP का 10%। अब ये कोड सेक्स वर्क को फॉर्मल इकोनॉमी में लाएगा। लेकिन विवाद भी हुआ। कुछ ने इसे क्रिमिनल एक्ट्स को बढ़ावा देने वाला कहा, जैसे ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन, जो इटली में बैन है। सेक्स वर्कर्स ग्रुप्स इसे सकारात्मक मानते हैं, कहते हैं इससे हेल्थ और सेफ्टी बेहतर होगी। पहले वो 'मसाज' कोटि यूज करती थीं। गवर्नमेंट ने कहा ये डेटा कलेक्शन के लिए है, डिक्रिमिनलाइजेशन नहीं। लेकिन ये स्टेप डिक्रिमिनलाइजेशन की तरफ इशारा करता है। नीदरलैंड्स जैसे देशों से तुलना में इटली अब पीछे नहीं। आलोचक कहते हैं कि ये शोषण को वैध बनाएगा, खासकर माइग्रेंट महिलाओं का। 2023 में बोलोग्ना में सेक्स वर्कर्स ने डिक्रिमिनलाइजेशन की मांग की। NAP 2022-2025 ट्रैफिकिंग रोकने पर फोकस करता है। ये कोड बहस छेड़ रहा है कि क्या सेक्स वर्क को जॉब मानना चाहिए? इटली समाज को ये दिखा रहा है कि छोटे बदलाव से बड़ी तब्दीली आ सकती है, लेकिन नैतिक सवाल बाकी हैं।

बहस का दूसरा पहलू: फायदे तो हैं, लेकिन जोखिम भी कम नहीं

फ्रांस और इटली के इन कदमों से बहस तेज हो गई है- क्या यौन व्यापार को ढील देना महिलाओं की मदद करेगा या नुकसान? एक तरफ, सेक्स वर्कर्स को अधिकार मिलेंगे: हेल्थ चेक, लीगल प्रोटेक्शन, टैक्स से पेंशन। बेल्जियम ने 2022 में डिक्रिमिनलाइजेशन किया, सेक्स वर्कर्स को पेड लीव मिला। EU में ट्रैफिकिंग कम करने के लिए नॉर्डिक मॉडल ठीक था, लेकिन अब स्टडीज कहती हैं कि सख्ती ने वर्कर्स को और खतरे में डाला। दूसरी तरफ, आलोचक चेताते हैं कि ब्रोथल्स शोषण के हॉटस्पॉट बन सकते हैं। फ्रांस में RN का प्रस्ताव पॉपुलिस्ट लगता है, लेकिन असल में विदेशी वर्कर्स को टारगेट कर सकता है। इटली का कोड अच्छा है, लेकिन बिना रेगुलेशन के ट्रैफिकर्स फायदा उठाएंगे। EU रिपोर्ट्स कहती हैं कि 70% पीड़ित महिलाएं हैं, ज्यादातर माइग्रेंट। बैलेंस्ड व्यू में, डेटा-ड्रिवन पॉलिसी चाहिए: वर्कर्स से बातचीत, एग्जिट प्रोग्राम्स। ह्यूमन राइट्स वॉच कहता है कि राइट्स-बेस्ड अप्रोच अपनाएं। क्या ये बदलाव समाज को नॉर्मलाइज करेगा या नैतिक गिरावट लाएगा? फ्रांस-इटली ये दिखा रहे हैं कि पुरानी पाबंदियां पर्याप्त नहीं। लेकिन बिना मजबूत सेफगार्ड्स के ये खतरनाक हो सकता है। समाज को सोचना होगा: क्या हम वर्कर्स को एम्पावर करेंगे या इग्नोर? ये बहस जारी रहेगी, और शायद EU-वाइड रिफॉर्म लाएगी।

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो बने पवित्र शहर

शराब, मांस और तंबाकू पर लगेगी सख्त रोक

@ आनंद मीणा

पंजाब सरकार ने राज्य के धार्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप को लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। सरकार ने अमृतसर के चारदीवारी क्षेत्र, श्री आनंदपुर साहिब नगर और तलवंडी साबो नगर को आधिकारिक रूप से "पवित्र शहर" घोषित कर दिया है। इस फैसले के साथ ही इन तीनों शहरों में शराब, मांस, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री और उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।सरकार का कहना है कि यह कदम सिख धर्म से जुड़े इन प्रमुख तीर्थ स्थलों की धार्मिक गरिमा, पवित्रता और ऐतिहासिक पहचान को बनाए रखने के लिए जरूरी था। लंबे समय से धार्मिक संगठनों और श्रद्धालुओं की ओर से ऐसी मांग उठती रही है कि इन शहरों में नशे और मांसाहार जैसी गतिविधियों पर रोक लगाई जाए।

राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी

इस फैसले को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद आधिकारिक रूप से लागू किया गया है। पंजाब सरकार के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आलोक शेखर द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राज्यपाल को यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अमृतसर जिले का चारदीवारी क्षेत्र, रूपनगर जिले का श्री आनंदपुर साहिब नगर और बठिंडा जिले का तलवंडी साबो नगर अब पंजाब राज्य के पवित्र शहर घोषित किए जाते हैं।अधिसूचना में साफ तौर पर कहा गया है कि इन क्षेत्रों की नगरपालिका सीमाओं के भीतर अब ऐसे सभी कार्यों और व्यवसायों पर रोक लगेगी, जो इन शहरों की धार्मिक भावना और पवित्रता के खिलाफ माने जाते हैं।

शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध की तैयारी

पवित्र शहर घोषित किए जाने के बाद सबसे बड़ा असर शराब की बिक्री और उपयोग पर पड़ने वाला है। सरकार ने आबकारी विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इन तीनों शहरों की नगर सीमा के भीतर शराब और उससे जुड़े सभी उत्पादों की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए जाएं।सूत्रों के मुताबिक, जल्द ही शराब के मौजूदा ठेकों को बंद करने या फिर नगर सीमा से बाहर स्थानांतरित करने को लेकर अलग से अधिसूचना जारी हो सकती है। इससे पहले भी अमृतसर के गोल्डन टेंपल के आसपास के इलाकों में शराब की बिक्री को लेकर विवाद सामने आते रहे हैं।सरकार का मानना है कि धार्मिक स्थलों के आसपास शराब की उपलब्धता न केवल आस्था को ठेस पहुंचाती है, बल्कि सामाजिक समस्याओं को भी जन्म देती है।

सिगरेट, तंबाकू और नशे पर भी शिकंजा

इस फैसले में केवल शराब ही नहीं, बल्कि सिगरेट, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों को भी प्रतिबंध के दायरे में लाया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि इन पवित्र शहरों में तंबाकू और नशीले पदार्थों की बिक्री और उपयोग पर रोक लगाने के लिए जरूरी आदेश जारी किए जाएं।सरकार का तर्क है कि नशे के खिलाफ यह कदम न केवल धार्मिक दृष्टि से अहम है, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिहाज से भी जरूरी है। खासतौर पर युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने के लिए इसे एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है।

मांस की बिक्री और सेवन पर भी रोक

धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पशुपालन विभाग को भी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि अमृतसर के चारदीवारी क्षेत्र, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो की नगरपालिका सीमाओं के भीतर मांस और उससे जुड़े उत्पादों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए जाएं।सिख धर्म में इन स्थानों का विशेष धार्मिक महत्व है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं। सरकार का मानना है कि मांस की बिक्री और सेवन पर रोक से इन शहरों का धार्मिक माहौल और अधिक शांत और पवित्र बना रहेगा।

स्थानीय प्रशासन को सख्त निर्देश

इस फैसले को जमीन पर लागू करने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन को दी गई है। स्थानीय सरकार विभाग को अधिसूचना भेजकर जरूरी कार्रवाई करने को कहा गया है। इसके साथ ही अमृतसर, रूपनगर और बठिंडा के उपायुक्तों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में इस फैसले को प्रभावी ढंग से लागू करें।माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में नगर निगम और जिला प्रशासन स्तर पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। इसमें यह साफ किया जाएगा कि किन इलाकों में प्रतिबंध लागू होगा, उल्लंघन पर क्या कार्रवाई होगी और व्यापारियों के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है।

धार्मिक महत्व से जुड़ा फैसला

सरकार के इस कदम को इन तीनों शहरों के गहरे धार्मिक महत्व से जोड़कर देखा जा रहा है। अमृतसर सिख धर्म का सबसे बड़ा और पवित्र केंद्र है, जहां श्री हरमंदिर साहिब स्थित है। दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु यहां मत्था टेकने आते हैं।श्री आनंदपुर साहिब सिख इतिहास में खास स्थान रखता है। यहीं पर खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। वहीं तलवंडी साबो, जिसे श्री दमदमा साहिब के नाम से भी जाना जाता है, सिख धर्म के पांच तख्तों में से एक है। ऐसे में इन शहरों को पवित्र घोषित करना सिख समुदाय की भावनाओं से सीधा जुड़ा हुआ फैसला माना जा रहा है।

समर्थन और बहस दोनों

सरकार के इस फैसले का कई धार्मिक संगठनों और सिख संस्थाओं ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे आने वाली पीढ़ियों को इन धार्मिक स्थलों की पवित्रता और ऐतिहासिक महत्व का सही संदेश मिलेगा।हालांकि, कुछ व्यापारिक संगठनों और स्थानीय कारोबारियों की ओर से चिंता भी जताई जा रही है। उनका कहना है कि अचानक प्रतिबंध से रोज़गार और व्यवसाय पर असर पड़ सकता है। ऐसे में सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था और संक्रमण काल देना चाहिए।

सरकार का रुख साफ

पंजाब सरकार का कहना है कि यह फैसला किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था और सामाजिक भलाई को ध्यान में रखकर लिया गया है। सरकार का दावा है कि स्थानीय लोगों और व्यापारियों से बातचीत कर धीरे-धीरे इसे लागू किया जाएगा, ताकि किसी को अनावश्यक परेशानी न हो।सरकार के मुताबिक, पवित्र शहरों की पहचान केवल धार्मिक स्थलों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूरे शहर का माहौल आस्था, शांति और अनुशासन से भरा होना चाहिए। यही सोच इस फैसले के पीछे की सबसे बड़ी वजह है।

इलॉन मस्क ने रचा इतिहास

600 बिलियन डॉलर की दौलत, स्पेसएक्स से बदली दुनिया की अमीरी

@ सौम्या चौबे

दुनिया की दौलत का नक्शा एक बार फिर बदल गया है। टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में लगातार प्रयोग करने वाले इलॉन मस्क अब आधिकारिक रूप से दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए हैं। उनकी कुल संपत्ति 600 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर चुकी है। भारतीय मुद्रा में यह रकम करीब 54.5 लाख करोड़ रुपये बैठती है। इस मुकाम तक पहुंचने वाले मस्क दुनिया के पहले व्यक्ति हैं।यह बढ़ोतरी किसी लॉटरी या अचानक मिले फायदे का नतीजा नहीं है, बल्कि इसके पीछे वर्षों की जोखिम भरी रणनीति, असफलताओं से भरा सफर और भविष्य को लेकर बड़ा सपना है। एक ही दिन में मस्क की संपत्ति में करीब 168 बिलियन डॉलर की छलांग लगी। यह रकम भारत के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी की कुल नेटवर्थ से भी ज्यादा है।

स्पेसएक्स ने बदली मस्क की किस्मत

स्पेसएक्स को लेकर बाजार में लंबे समय से चर्चा थी कि कंपनी जल्द आईपीओ ला सकती है। इसी बीच कंपनी के भीतर हुई शेयर बिक्री ने इसकी वैल्यूएशन को 800 बिलियन डॉलर तक पहुंचा दिया। यह आंकड़ा स्पेसएक्स को दुनिया की सबसे मूल्यवान प्राइवेट कंपनी बना देता है।इलॉन मस्क के पास स्पेसएक्स में करीब 42 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इस हिसाब से सिर्फ स्पेसएक्स में उनकी हिस्सेदारी की कीमत 330 बिलियन डॉलर से ज्यादा बैठती है। अगर भविष्य में कंपनी इसी वैल्यूएशन पर शेयर बाजार में लिस्ट होती है और निवेशकों का भरोसा बना रहता है, तो मस्क की संपत्ति और तेजी से बढ़ सकती है।फोर्ब्स जैसे प्रतिष्ठित बिजनेस मैगजीन का मानना है कि स्पेसएक्स के सफल आईपीओ के बाद इलॉन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर भी बन सकते हैं। हालांकि यह पूरी तरह बाजार के रुख और लिस्टिंग की सफलता पर निर्भर करेगा।

197 बिलियन डॉलर है कीमत

स्पेसएक्स के अलावा मस्क की संपत्ति में बड़ा योगदान उनकी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला का भी है। टेस्ला में उनकी हिस्सेदारी करीब 12 प्रतिशत है। 2025 में अब तक टेस्ला के शेयरों में लगभग 13 प्रतिशत की तेजी देखी जा चुकी है। हाल ही में मस्क ने बताया कि टेस्ला बिना सेफ्टी मॉनिटर के रोबोटैक्सी का परीक्षण कर रही है।

इस बयान के बाद बाजार में उत्साह दिखा और शेयरों में चार प्रतिशत तक की बढ़त दर्ज की गई। टेस्ला में मस्क की हिस्सेदारी की मौजूदा कीमत करीब 197 बिलियन डॉलर आंकी जा रही है।

इसके अलावा उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी xAI भी निवेशकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। xAI करीब 230 बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन पर 15 बिलियन डॉलर की नई फंडिंग जुटाने की तैयारी में है। अगर यह डील पूरी होती है, तो मस्क की नेटवर्थ को एक और बड़ा सहारा मिलेगा।

बचपन से ही अलग सोच वाले मस्क

इलॉन मस्क की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। उन्होंने महज 10 साल की उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख ली थी। 12 साल के थे, जब उन्होंने 'ब्लास्टर' नाम का एक वीडियो गेम बनाया और उसे 500 डॉलर में बेच दिया। यही उनकी पहली कमाई थी और यहीं से यह साफ हो गया था कि यह बच्चा साधारण नहीं है।1995 में मस्क ने अपने भाई के साथ मिलकर वेब सॉफ्टवेयर कंपनी जिप-2 की शुरुआत की। उस समय इंटरनेट नया-नया था और जोखिम बहुत बड़ा। लेकिन 1999 में कॉम्पेक ने इस कंपनी को 307 मिलियन डॉलर में खरीद लिया। मस्क को इस सौदे से करीब 22 मिलियन डॉलर मिले। यही वह मोड़ था, जिसने उनके भविष्य की दिशा तय की।

पेपाल से मिली पहचान, स्पेसएक्स से मिली उड़ान

जिप-2 के बाद मस्क ने ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम पेपाल की नींव रखी। यह आइडिया उस दौर में क्रांतिकारी माना गया। 2002 में ईबे ने पेपाल को 1.5 अरब डॉलर में खरीद लिया। इस सौदे से मस्क को करीब 180 मिलियन डॉलर मिले।यहीं से उन्होंने वह कदम उठाया, जिसे उस समय कई लोग पागलपन मानते थे। उन्होंने अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने की कंपनी स्पेसएक्स शुरू की। शुरुआती तीन लॉन्च असफल रहे। पैसा खत्म होने की कगार पर था। आलोचकों ने ताने कसे। लेकिन चौथा लॉन्च सफल हुआ और वहीं से इतिहास बदल गया।आज स्पेसएक्स नासा के लिए मिशन उड़ाती है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक कार्गो पहुंचाती है और मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने का सपना देख रही है।

टेस्ला से बदली ऑटो इंडस्ट्री

टेस्ला की स्थापना मस्क ने नहीं की थी, लेकिन उन्होंने इसे पहचान जरूर दी। 2004 में भारी निवेश के बाद मस्क कंपनी के चेयरमैन बने और फिर सीईओ। उस समय इलेक्ट्रिक कार को लेकर लोगों में संदेह था। लेकिन मस्क ने इसे भविष्य की जरूरत बताया।आज टेस्ला दुनिया की सबसे चर्चित इलेक्ट्रिक कार कंपनी है। इसने न सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री को बदला, बल्कि सस्टेनेबल एनर्जी पर पूरी दुनिया का ध्यान खींचा।2016 में मस्क ने न्यूरालिंक की शुरुआत की। इसका उद्देश्य इंसानी दिमाग और कंप्यूटर के बीच सीधा संपर्क बनाना है। न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के इलाज से लेकर इंसान और एआई के रिश्ते को नया रूप देने तक, न्यूरालिंक मस्क के दूरदर्शी सोच का उदाहरण है।

दौलत से ज्यादा सपना

इलॉन मस्क की यह 600 बिलियन डॉलर की दौलत सिर्फ आंकड़ा नहीं है। यह उस सोच का नतीजा है, जिसमें जोखिम उठाना, असफल होना और फिर उससे भी बड़े सपने देखना शामिल है। मस्क खुद कई बार कह चुके हैं कि पैसा उनके लिए लक्ष्य नहीं है, बल्कि साधन है।आज जब दुनिया उन्हें सबसे अमीर इंसान के तौर पर देख रही है, मस्क मंगल, एआई और मानव भविष्य की बातें कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि उनकी कहानी सिर्फ अमीरी की नहीं, बल्कि सोच की उड़ान की कहानी बन जाती है।

दुनिया विस्तृत रंगमंच है

अच्छे होने की एक बड़ी समस्या यह भी है
कि आपको किसी की अच्छाई पर संशय नहीं होता।

आपको लगता है गर यह दुनिया है तो इसी दुनिया में
कहीं न कहीं अच्छे लोग ज़रूर उपस्थित हैं।

आप मानते हैं कि लोगों को अच्छा होना ही चहिए।
आप हर जगह केवल अच्छाई तलाशते हैं।

इस सत्य के प्रति आँखें मूँदकर कि अगर दुनिया वाकई
अच्छी होती
तो आप अकेले न होकर किसी भीड़ में हँस-गा रहे होते।

आप मंत्रमुग्ध मोर का नाच देखते हैं।
अमुक आएँगे बताएँगे देखो इसके पैर कैसे कुरूप हैं।

आप कहेंगे लेकिन नाच कैसा सुंदर
वो कहेंगे हुँह पैर तो देखो।

आपका मन उचट जाएगा।
पैरों की कुरूपता से नहीं।

उनकी विचारों की कुरूपता से।
अब आप पुनः नाच देखने लगते हैं तो ध्यान देते हैं।

पैरों पर नहीं, रंगों पर।
पंखों के मोहक रंग सब नकली है।

नहीं-नहीं पूरे पंख ही नकली हैं।
आँखों में कुछ किरकिराता है।

आप आँख रगड़ते हैं। पुनः खोलते हैं।
सामने क़रीने से पंख रखे हैं

और एक कुरूप वीभत्स जीव
बेध्यानी में गहरी साँसें ले रहा है।

आपके गले में कुछ फँसता है। इसे निगल लीजिए।
रुकिए, कहीं जाइए नहीं। जीव उठता है।

नफ़ासत से एक एक पंख सजाता है।
अब नाच स्टेज पर हो रहा है।

आप वापस लौटना चाहते हैं?
माफ़ कीजिए। नहीं जा सकते।

आप अदृश्य धागों से बँध चुके हैं।
आप अपनी पूरी शक्ति लगाकर बंधन तोड़ देते हैं।

पुनः माफ़ी। आप अभी भी नहीं जा सकते।
आपकी तमाम कोशिशों को नकारती

भीड़ आपको भीतर धकेल देती है।
हॉल खचा-खच भर चुका है।

लोग नृत्य की प्रशंसा में ताली बजा रहे हैं।
जिन्होंने पैरों की कुरूपता दिखाई थी,

वे वंस मोर वंस मोर चिल्ला रहे हैं।
मंचन स्टेज पर भी है स्टेज के नीचे भी।

आप किस के लिए ताली बजाना चाहते हैं?
दुविधा में हैं? कोई नहीं पंख वही रहेंगे। नर्तक बदलते
जाएँगे।

नृत्य वही जारी है। आप ऊब गए? एकांत चाहते हैं।
माफ़ कीजिए। क्या आप देख नहीं पा रहे

कि अब हॉल में सबके पास सुंदर पंख हैं।
वे सब मित्र हैं और मित्रता स्थायी करने के लिए

एक साझा शत्रु आवश्यक है।
उन सबकी अँगुलिया आपकी ओर उठी हैं।

फुसफुसाहट में आपका नाम है।
माफ़ कीजिए। नहीं, माफ़ी माँग लीजिए।

क्या आप अभी तक समझ नहीं पाए?
छद्म पंखों की इस महफ़िल में आप सबसे कुरूप इंसान हैं।

गीत

अधरों पर मुस्कान सजी है आँखों में ठहरा पानी है,
मन सब बिसरे स्वप्न जगाता मन की कैसी नादानी है।

चलता ज़ोर न कोई मन पर मन ने कब किसकी मानी है,
उन्हें देख उनका हो जाता मन करता बेईमानी है।

अधरों पर मुस्कान सजी है आँखों में ठहरा पानी है,
मन सब बिसरे स्वप्न जगाता मन की कैसी नादानी है।

इस अदय संसार ने बोलो कब पीर दिलों की जानी है,
ख़ुद को खोकर ख़ुद ही पाना ये रीत उन्हें अनजानी है।

अधरों पर मुस्कान सजी है आँखों में ठहरा पानी है,
मन सब बिसरे स्वप्न जगाता मन की कैसी नादानी है।

जीत हार की बातें करना दिल को लगता बेमानी है,
किस पाले में मैं हो जाऊँ ख़ुद से ख़ुद खींचा-तानी है।

अधरों पर मुस्कान सजी है आँखों में ठहरा पानी है,
मन सब बिसरे स्वप्न जगाता मन की कैसी नादानी है।

बिना बात मैं हँसती जाऊँ जग को लगता दीवानी है,
भेद न कोई यह पा पाए दिन में महकी रतरानी है।

अधरों पर मुस्कान सजी है आँखों में ठहरा पानी है,
मन सब बिसरे स्वप्न जगाता मन की कैसी नादानी है।

निधि अग्रवाल
(नई पीढ़ी की सुपरिचित कवयित्री।)

मनरेगा खत्म, नया ग्रामीण रोजगार कानून आया

125 दिन काम नाम बदला सियासत गरम

@ रिंकू विश्वकर्मा

ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने वाली सबसे बड़ी योजनाओं में शामिल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून अब इतिहास बनने की ओर बढ़ रहा है। मोदी सरकार इसे पूरी तरह खत्म कर एक नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने जा रही है। सरकार ने इस नए कानून को मौजूदा शीतकालीन सत्र में चर्चा के लिए सूचीबद्ध कर दिया है और इसकी प्रति लोकसभा सांसदों के बीच भी सर्कुलेट कर दी गई है। प्रस्तावित कानून का नाम रखा गया है,विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल, 2025।यह सिर्फ नाम बदलने की कवायद नहीं है, बल्कि सरकार का दावा है कि यह ग्रामीण रोजगार और आजीविका को लेकर पूरी सोच में बदलाव का संकेत है। जहां मनरेगा पिछले बीस वर्षों से ग्रामीण परिवारों के लिए जीवनरेखा बनी रही, वहीं नया कानून 'विकसित भारत 2047' के विजन के तहत गांवों के समग्र विकास का खाका पेश करता है।

100 दिन से 125 दिन तक रोजगार का वादा

नए बिल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें रोजगार के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि बीते दो दशकों में ग्रामीण भारत की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में बड़ा बदलाव आया है। अब सिर्फ अस्थायी मजदूरी नहीं, बल्कि आजीविका की स्थिरता और गांवों की उत्पादक क्षमता बढ़ाने की जरूरत है।बिल के उद्देश्य में साफ लिखा गया है कि हर ऐसा ग्रामीण परिवार, जिसका कोई वयस्क सदस्य बिना कौशल वाला काम करने को तैयार है, उसे साल में 125 दिन का वेतनयुक्त रोजगार देने की गारंटी दी जाएगी। सरकार के मुताबिक यह कदम गांवों को आत्मनिर्भर बनाने और पलायन रोकने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।

मनरेगा पूरी तरह खत्म होगी

इस बिल को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मनरेगा और नया कानून साथ-साथ चलेंगे या नहीं। इसका जवाब बिल में साफ तौर पर दिया गया है। प्रस्तावित कानून 2005 के मनरेगा कानून को पूरी तरह रद्द करता है। यानी नया कानून लागू होते ही मनरेगा समाप्त हो जाएगी और उसकी जगह सिर्फ VB-G RAM G लागू रहेगा।सरकार का तर्क है कि मनरेगा ने अपने समय में अहम भूमिका निभाई, लेकिन बदलते हालात में उसे नए ढांचे में ढालना जरूरी हो गया था। इसलिए एक नया कानून लाकर ग्रामीण रोजगार नीति को नए सिरे से परिभाषित किया जा रहा है।

डिजिटल पहचान और नया पंजीकरण

नया कानून लागू होने की प्रक्रिया भी चरणबद्ध होगी। संसद से पास होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा। इसके बाद राज्यों को छह महीने का समय मिलेगा, ताकि वे अपनी-अपनी योजनाएं तैयार कर सकें।सबसे बड़ा बदलाव पंजीकरण व्यवस्था में होगा। पुराने जॉब कार्ड की जगह अब डिजिटल और बायोमेट्रिक आधारित पहचान प्रणाली लाई जाएगी। यानी मजदूरों का पंजीकरण, उपस्थिति और भुगतान पूरी तरह तकनीक आधारित होगा। सरकार का दावा है कि इससे फर्जी जॉब कार्ड, बिचौलियों और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।

मजदूरी दर पर अभी सस्पेंस

जहां रोजगार के दिनों की संख्या बढ़ाने की बात कही गई है, वहीं मजदूरी दर को लेकर बिल में कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं दिया गया है। इसका मतलब यह है कि मजदूरी दरें केंद्र और राज्य सरकारें अलग-अलग तय करेंगी, जैसा कि अभी मनरेगा में होता है।विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मजदूरी दरों में ठोस बढ़ोतरी नहीं हुई, तो 125 दिन का रोजगार भी मजदूरों के लिए पर्याप्त राहत नहीं बन पाएगा। फिलहाल इस सवाल का जवाब कानून के लागू होने के बाद ही साफ हो पाएगा।

काम मिलेगा, लेकिन शर्तों के साथ

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 125 दिन का रोजगार सभी को अपने-आप नहीं मिलेगा। इसके लिए कुछ शर्तें होंगी। परिवार ग्रामीण क्षेत्र का होना चाहिए। परिवार का कोई वयस्क सदस्य बिना कौशल वाला श्रम करने को तैयार हो। रोजगार केवल सरकार द्वारा तय सार्वजनिक कार्यों में ही मिलेगा।यानी यह मांग आधारित रोजगार व्यवस्था होगी। मजदूर को काम मांगना होगा और सरकार उसे तय समय में काम उपलब्ध कराएगी।

बोवाई और कटाई के समय क्या होगा

ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर यह समस्या सामने आती है कि सरकारी काम और खेती के मौसम एक-दूसरे से टकरा जाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए नए बिल में राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वे बोवाई और कटाई के समय कुछ अवधि के लिए सरकारी काम अस्थायी रूप से रोक सकें।सरकार का तर्क है कि इससे खेतों में मजदूरों की कमी नहीं होगी और किसान तथा मजदूर दोनों को नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। यानी खेती के मौसम में मजदूर खेतों में काम करेंगे और सरकारी रोजगार बाद में उपलब्ध कराया जाएगा।

कांग्रेस का विरोध और गांधी नाम का सवाल

सरकार के इस फैसले पर विपक्ष खासकर कांग्रेस ने तीखा विरोध जताया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि इस नाम परिवर्तन की जरूरत क्यों पड़ी।प्रियंका गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी का नाम हटाने से न सिर्फ प्रतीकात्मक नुकसान होता है, बल्कि सरकारी संसाधनों की भी बर्बादी होती है। ऑफिस की फाइलें, स्टेशनरी, दस्तावेज़-सब कुछ दोबारा बदलना पड़ता है, जो एक महंगी प्रक्रिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इससे हासिल क्या होगा।

नाम बदलने की पुरानी राजनीति

कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार पिछले 11 वर्षों से UPA सरकार की योजनाओं के नाम बदलकर उन्हें अपना बताने की नीति पर चल रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक वीडियो जारी कर कहा कि मनरेगा को कभी कांग्रेस की विफलता बताया गया था, लेकिन आज वही योजना ग्रामीण भारत की संजीवनी साबित हुई है।सुप्रिया ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार की शुरू की गई 32 से अधिक योजनाओं के नाम बदले गए हैं और उन्हें नए ब्रांड के तौर पर पेश किया गया है। उनके मुताबिक यह सिर्फ नाम बदलने की राजनीति है, जबकि ज़मीनी सच्चाई यह है कि योजनाओं की आत्मा वही रहती है।

सरकार का तर्क

सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि यह बदलाव सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि नीतिगत है। नए कानून के जरिए रोजगार को आजीविका मिशन से जोड़ा जाएगा। गांवों में स्थायी संपत्तियों का निर्माण, कौशल विकास और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर ज़ोर होगा।

सरकार का दावा है कि यह कानून ग्रामीण भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। हालांकि विपक्ष का मानना है कि मनरेगा जैसे स्थापित कानून को खत्म करना गरीबों के लिए जोखिम भरा हो सकता है।

कहानी अभी बाकी है

मनरेगा ने गांवों में भूख, बेरोजगारी और पलायन के खिलाफ एक सुरक्षा कवच की तरह काम किया है। अब जब सरकार इसे खत्म कर नया कानून लाने जा रही है, तो सवाल सिर्फ रोजगार के दिनों का नहीं, बल्कि भरोसे का भी है।

यह भरोसा कि गांव के सबसे गरीब परिवार को मुश्किल वक्त में काम मिलेगा। यह भरोसा कि कानून सिर्फ कागज़ों तक सीमित नहीं रहेगा। संसद में होने वाली चर्चा और आने वाले महीनों में राज्यों की तैयारी तय करेगी कि यह नया कानून ग्रामीण भारत के लिए उम्मीद बनेगा या एक नई बहस की शुरुआत।

फिलहाल इतना तय है कि ग्रामीण रोजगार की कहानी एक नए मोड़ पर खड़ी है। यह मोड़ गांवों को मजबूत करेगा या नई चुनौतियां खड़ी करेगा, इसका जवाब वक्त देगा।

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

नेपाल में फिर भड़क सकता है युवाओं का आक्रोश

नई सरकार, पुराने अफसर, 100 दिन बाद भी वादे अधूरे

नेपाल में सितंबर 2025 का वह महीना था जब युवाओं का गुस्सा एक छोटी सी चिंगारी से फैल गया और पूरे देश को हिला दिया। सब कुछ शुरू हुआ 6 सितंबर को जब एक मंत्री के वाहन ने काठमांडू में एक 11 साल की बच्ची को टक्कर मार दी और भाग गया। प्रधानमंत्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओली ने इसे 'सामान्य दुर्घटना' बता दिया, लेकिन युवा इससे सहमत नहीं हुए। सोशल मीडिया पर #NepoBaby जैसे अभियान चले जहां अमीर नेताओं के बच्चों की लग्जरी लाइफ दिखाई गई, जबकि लाखों युवा बेरोजगारी और गरीबी से जूझ रहे थे। नेपाल में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या आधी आबादी से ज्यादा है, और युवा इंस्टाग्राम, टिकटॉक, डिस्कॉर्ड जैसे प्लेटफॉर्म पर सक्रिय थे। 4 सितंबर को सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर था ताकि कंटेंट की निगरानी हो सके। लेकिन यह बैन उल्टा पड़ा। युवा नेता सुडान गुरुंग ने इंस्टाग्राम पर विरोध की अपील की, और 8 सितंबर को 'यूथ अगेंस्ट करप्शन' डिस्कॉर्ड चैनल पर लाखों युवा जुड़े। सड़कों पर शांतिपूर्ण विरोध शुरू हुआ, लेकिन पुलिस की गोलीबारी में 19 से ज्यादा युवा मारे गए, ज्यादातर 30 साल से कम उम्र के। इसके बाद गुस्सा भड़क गया। भीड़ ने संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, मंत्रालयों और पार्टियों के दफ्तर जला दिए। कम से कम 77 लोग मारे गए, जिसमें पुलिस वाले भी शामिल थे। आर्थिक नुकसान 586 मिलियन डॉलर का हुआ, और पर्यटन पर 18 फीसदी की गिरावट आई। यह आंदोलन सिर्फ युवाओं का नहीं था, बल्कि छात्र, प्रोफेशनल और बुजुर्ग भी जुड़े। यह नेपाल के इतिहास का तीसरा बड़ा जन आंदोलन था, 1990 और 2006 के बाद। युवाओं ने 'वन पीस' कार्टून के जॉली रोजर झंडे लहराए, जो तानाशाही से आजादी का प्रतीक था। वीडियो वायरल हुए, और 10 सितंबर को डिस्कॉर्ड पर 7586 युवाओं ने वोटिंग की जिसमें पूर्व चीफ जस्टिस सुशिला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री चुना गया। पुरानी सरकार गिर गई, संसद भंग हो गई, और पहली बार एक महिला प्रधानमंत्री बनीं। लेकिन सवाल यह था कि क्या यह बदलाव सतही था? युवाओं का गुस्सा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और असमानता से उपजा था। नेपाल की जीडीपी ग्रोथ 5.1 फीसदी से घटकर 2.1 फीसदी रह गई, और युवा बेरोजगारी 22.7 फीसदी थी। अमीरों की कमाई 1995 से 13 गुना बढ़ी, जबकि गरीबों की सिर्फ 30 गुना। यह आंदोलन क्षेत्रीय था, बांग्लादेश 2024 और श्रीलंका 2022 जैसे आंदोलनों से प्रेरित। लेकिन अब, तीन महीने बाद, क्या कुछ बदला? युवा कहते हैं, सरकार तो बदली, लेकिन सिस्टम वही पुराना। यह कहानी सिर्फ नेपाल की नहीं, बल्कि उन लाखों युवाओं की है जो भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन क्या उनका सपना पूरा होगा या फिर सड़कें फिर गर्म होंगी?

नई सरकार, पुरानी जड़ें: अंतरिम व्यवस्था की उम्मीदें और हकीकत

10 सितंबर 2025 को जब सुशिला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री बनीं, तो नेपाल में एक नई उम्मीद जगी। यह 'आवश्यकता के सिद्धांत' पर आधारित था, जहां राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने संसद भंग होने के बाद यह कदम उठाया। कार्की पहली महिला पीएम बनीं, जो दक्षिण एशिया में तीसरा ऐसा उदाहरण था जहां युवा आंदोलन ने सरकार गिराई। अंतरिम सरकार का मुख्य काम था नए चुनाव कराना, भ्रष्टाचार की जांच, और संस्थाओं में सुधार। युवाओं की मांग थी कि सरकारी नौकरियां योग्यता पर हों, न कि राजनीतिक कनेक्शन पर। आंदोलन के बाद सेना को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि पुरानी मशीनरी ढह चुकी थी। जेलों से हजारों कैदी गायब हो गए, और 1100 से ज्यादा हथियार लूट लिए गए। सरकार ने न्यायिक आयोग बनाया ताकि हिंसा और भ्रष्टाचार की जांच हो। लेकिन चुनौतियां कम नहीं थीं। पुरानी पार्टियां जैसे नेपाली कांग्रेस, सीपीएन-यूएमएल और माओवादी अभी भी सत्ता में दखल रखे हुए हैं। भ्रष्टाचार के केस जैसे पोखरा एयरपोर्ट में 14 अरब रुपए का घोटाला, वीजा स्कैम और कोऑपरेटिव फाइनेंस कंपनियों का फंड चोरी अभी भी उजागर हो रहे थे। अंतरिम सरकार ने चुनाव 5 मार्च 2026 को तय किए, जिसमें डायस्पोरा को वोटिंग का अधिकार और वोटर लिस्ट सुधार शामिल है। युवाओं ने मांगा कि हेड ऑफ स्टेट सीधे चुना जाए, टर्म लिमिट हो, और न्यूनतम उम्र 21 साल हो उम्मीदवार बनने की। लेकिन हकीकत यह है कि नौकरशाही वही पुरानी है। युवा नेता टंका धामी कहते हैं, 'सरकार बदली, लेकिन अफसर वही हैं जो पुरानी व्यवस्था चला रहे थे।' यह पुरानी जड़ें सुधारों को रोक रही हैं। आर्थिक मोर्चे पर रेमिटेंस 75 फीसदी घरों को चलाती है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय 1500 डॉलर से कम है। 15,000 नौकरियां चली गईं, और पुनर्निर्माण का खर्च 252 मिलियन डॉलर है। अंतरराष्ट्रीय मदद आई, भारत, अमेरिका और दलाई लामा के प्रशासन से, लेकिन चीन को चिंता है अगर कम्युनिस्ट पार्टियां हारें। युवा डिविजन में भी बंटे हैं, कुछ राजशाही चाहते हैं, कुछ फेडरल स्ट्रक्चर तोड़ना। अंतरिम सरकार ने कहा कि यह असाधारण परिस्थिति से बनी है, लेकिन क्या यह स्थिरता लाएगी? या पुरानी जड़ें फिर से उग आएंगी? यह सवाल नेपाल के भविष्य को छूता है, जहां बदलाव की चाहत है लेकिन रास्ता कठिन।

सितंबर का तूफान: सोशल मीडिया से सड़कें जल उठीं

100 दिन का इंतजार: वादों की बारिश, लेकिन सूखी जमीन

आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर नेपाल में उम्मीदें टूटने लगीं। सितंबर से दिसंबर तक सरकार ने कई वादे किए, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। युवा कहते हैं, 'कुछ नहीं बदला।' बेरोजगारी अभी भी 22.7 फीसदी है युवाओं में, और भ्रष्टाचार के केस बढ़ रहे हैं। एक किचन वर्कर कमल गौतम कहते हैं, 'तीन महीने से सैलरी नहीं मिली, परिवार कैसे चले?' पर्यटन में 18 फीसदी गिरावट आई, जो नेपाल की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा है। वर्ल्ड बैंक ने 2025 की जीडीपी ग्रोथ 2.1 फीसदी कर दी। सरकार ने कहा कि जांच आयोग बना दिया, लेकिन रिपोर्ट अभी आई नहीं। सुरक्षा एजेंसियों पर बल प्रयोग की जांच 90 दिनों में होनी थी, लेकिन देरी हो रही है। युवाओं की मांग थी कि राजनीतिक कोटा खत्म हो, लेकिन संस्थाओं में अभी भी पार्टियां दखल रखे हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2700 इमारतें और 2000 संस्थाएं प्रभावित हुईं, नुकसान 84.45 अरब रुपए का। अंतरिम सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर फोकस करने का वादा किया, लेकिन बजट में कटौती हो रही है। फेडरलिज्म और लोकल ऑटोनॉमी पर काम शुरू हुआ, लेकिन युवा भागीदारी कम है। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि पुरानी नौकरशाही बदलाव रोक रही है, क्योंकि नए कानून बनाने में समय लगता है। लेकिन युवा धैर्य खो चुके हैं। सोशल मीडिया पर फिर वीडियो शेयर हो रहे हैं जहां नेता परिवारों की फिजूलखर्ची दिखाई जा रही है। 100 दिनों में चुनावी सुधार जैसे NOTA ऑप्शन और प्राइमरी इलेक्शन की बात हुई, लेकिन अमल नहीं। न्यायपालिका में युवा प्रतिनिधित्व बढ़ाने का प्लान है, लेकिन अभी पुराने जज ही हैं। आर्थिक सुधार में स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है, लेकिन लोन और फंडिंग की कमी है। यह 100 दिन परीक्षा थे, जहां सरकार ने पारदर्शिता का वादा किया लेकिन संपत्ति घोषणा में देरी हो रही है। युवा सोचते हैं, क्या यह सिर्फ समय की देरी है या सिस्टम का बहाना? जमीन सूखी है, और बारिश के बादल भटक रहे हैं। नेपाल को अब फैसला करना है कि क्या सुधारों की राह अपनाए या फिर पुरानी गलतियां दोहराए।

युवा नेताओं की चेतावनी: 'फिर लड़ेंगे, अब चुप नहीं रहेंगे'

जनरेशन जेड के नेता अब खुलकर बोल रहे हैं कि 100 दिन बाद भी कुछ नहीं बदला, और अगर सुधार न हुए तो फिर सड़कों पर उतरेंगे। टंका धामी जैसे नेता कहते हैं, 'नौकरशाही वही पुरानी है, जो बदलाव को रोक रही। हम फिर लड़ेंगे।' सुडान गुरुंग, जो हमी नेपाल के एक्टिविस्ट हैं, ने कहा कि आंदोलन का स्पिरिट समझौतों में कैद नहीं हो सकता। 11 दिसंबर को जब 10-पॉइंट समझौता साइन हुआ, तो कुछ युवा नेताओं ने उसे फाड़ दिया। अजय सोराड़ी ने कहा, 'यह हमारे संघर्ष को कमजोर करता है।' समझौते में शहीदों को सम्मान, घायलों को मुफ्त इलाज-शिक्षा-रोजगार, संवैधानिक सुधार आयोग, भ्रष्टाचार रोकने के उपाय और चुनावी बदलाव जैसे NOTA शामिल हैं। लेकिन युवा कहते हैं, यह कागजी है। राखस्या बम और तशी ल्हाजोम जैसे नेता समर्थन में हैं, लेकिन मिराज धुंगाना ने बाद में इसे अस्वीकार कर दिया। प्रधानमंत्री कार्की ने कहा, 'युवा देश चलाएं,' और सुडान को 'बेटा' कहा, लेकिन इससे कुछ एक्टिविस्ट नाराज हो गए। युवा फ्रंट में फूट है, कुछ ग्रुप्स अलग हो गए। वे कहते हैं कि पुराने अफसर राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं, और भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। आंदोलन में 76 मौतें हुईं, ज्यादातर सिर और छाती में गोली लगी, जबकि नियम था घुटनों के नीचे फायरिंग। युवा नेता चेताते हैं कि अगर चुनाव से पहले सुधार न हुए तो अस्थिरता बढ़ेगी। वे मांग कर रहे हैं कि गैर-राजनीतिक अंतरिम सरकार बने, और जेन जेड काउंसिल सलाह दे। लेकिन क्या यह चेतावनी सुन ली जाएगी? युवा डिस्कॉर्ड पर फिर प्लानिंग कर रहे हैं, और वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक तरफ सरकार प्रयास कर रही है, दूसरी तरफ युवाओं का गुस्सा सही है। यह टकराव नेपाल को सोचने पर मजबूर करता है कि युवा आवाज दबानी है या सुननी है। अगर न सुनी गई, तो सड़कें फिर गरम हो सकती हैं।

मांसाहारी दूध का विवाद: ट्रंप के दूतों की मुस्कान के पीछे भारत का साहसी ऑफर

अमेरिकी गायों का रहस्य: दूध में छिपा 'नॉन-वेज' राज

अमेरिका और भारत के बीच व्यापार की बातें चल रही हैं, लेकिन बीच में एक अजीब सा मुद्दा आ खड़ा हुआ है – अमेरिकी गायों का दूध। हम सब जानते हैं कि गायें घास-चारे पर जीती हैं, लेकिन अमेरिका में मामला थोड़ा अलग है। वहां किसान अपनी गायों को ज्यादा दूध देने के लिए स्पेशल फीड देते हैं, जिसमें जानवरों की हड्डियों से बने एंजाइम जैसे रेनेट मिला होता है। भारत में इसे देखकर लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि यहां दूध को शुद्ध शाकाहारी माना जाता है। अगर गाय को नॉन-वेज खिलाया जाए, तो उसका दूध भी नॉन-वेज हो जाता है – यानी मांसाहारी दूध। धार्मिक भावनाओं के चलते लाखों लोग इसे स्वीकार नहीं कर पाते। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, जहां करोड़ों छोटे किसान अपनी आजीविका दूध पर चलाते हैं। अगर अमेरिकी दूध सस्ता आया, तो स्थानीय बाजार डगमगा सकता है। सरकार भी किसानों की रक्षा के लिए सख्ती बरत रही है। लेकिन व्यापार समझौते की दौड़ में क्या भारत झुकेगा? अमेरिका कहता है कि उसके डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे चीज, घी और दूध भारत के बाजार में घुसें, तो उसके किसान खुश होंगे। भारत की शर्त साफ है – हर प्रोडक्ट पर सर्टिफिकेट हो कि वो पूरी तरह शाकाहारी है। ये विवाद पुराना है, लेकिन 2025 में ट्रंप की दूसरी पारी में ये फिर गरमाया। दिसंबर तक बातें चल रही हैं, और भारत ने कुछ रियायतें देने का संकेत दिया है। ये ऑफर अमेरिकी पक्ष को इतना भाया कि उनके दूत मुस्कुरा उठे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये समझौता किसानों के हितों को बचाएगा, या बाजार की होड़ में भावनाएं दब जाएंगी? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि व्यापार सिर्फ पैसे का खेल नहीं, बल्कि संस्कृति और आजीविका का भी सवाल है।

ट्रंप का टैरिफ तीर: भारत पर क्यों चला 50 फीसदी का जख्म

डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के साथ अमेरिका-भारत रिश्ते फिर परीक्षा के दौर से गुजर रहे हैं। अगस्त 2025 में ट्रंप ने भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगाया, जो रूस से तेल खरीदने की सजा थी। इसके बाद 27 अगस्त को और 25 फीसदी एक्स्ट्रा टैरिफ जोड़ दिया, कुल मिलाकर 50 फीसदी। ये टैरिफ भारतीय सामानों जैसे कपड़े, जूते और मशीनरी पर लगे, जिससे निर्यातकों को भारी नुकसान हुआ। भारत का अमेरिका को निर्यात अप्रैल-जुलाई 2025 में 33.53 अरब डॉलर पहुंचा, लेकिन टैरिफ ने इसे मुश्किल बना दिया। ट्रंप का तर्क था कि भारत अमेरिकी सामानों पर ज्यादा टैक्स लगाता है, जबकि अमेरिका उदार है। लेकिन हकीकत में ये व्यापार असंतुलन का बदला था। भारत ने जवाब में अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर भी टैक्स बढ़ाने की धमकी दी, लेकिन बातचीत का रास्ता चुना। सितंबर में पहली बार अमेरिकी टीम दिल्ली आई, और बातें आगे बढ़ीं। नवंबर तक डील की उम्मीद थी, लेकिन दिसंबर 12 तक ये अधर में लटकी रही। टैरिफ से भारतीय किसानों और कारखानों को नुकसान हो रहा है – निर्यात घटा, नौकरियां खतरे में। लेकिन ये दबाव ने भारत को मजबूत बनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर कहा, 'किसानों के हितों पर कभी समझौता नहीं।' ट्रंप ने भी बैकफुट लिया, कहा कि रूसी तेल की खरीद कम हुई तो टैरिफ घटाएंगे। ये जंग सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि रणनीतिक भी है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके बाजार खोले, खासकर एग्रीकल्चर में। भारत ने GM फसलों और डेयरी पर सशर्त सहमति दिखाई, लेकिन मांसाहारी दूध पर अड़िग है। क्या ये टैरिफ युद्ध डील का रास्ता साफ करेगा, या और उलझन पैदा करेगा? ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि दोनों देशों के किसान बीच में फंस सकते हैं।

भारत का स्मार्ट ऑफर: डेयरी दरवाजा खुला, लेकिन ताले लगे

दिसंबर 10, 2025 को एक बड़ा ट्विस्ट आया जब अमेरिकी ट्रेड प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने कहा, 'भारत ने एग्रीकल्चर सेक्टर पर अब तक का सबसे अच्छा ऑफर दिया है।' ये ऑफर क्या है? भारत ने अमेरिकी सोयाबीन जैसे प्रोडक्ट्स को बाजार में बेचने की इजाजत देने का संकेत दिया, साथ ही डेयरी पर सशर्त खुलापन। लेकिन मांसाहारी दूध पर सख्त शर्त – हर आयातित प्रोडक्ट पर वेजिटेरियन सर्टिफिकेट जरूरी। अगर अमेरिका ये मान ले, तो सीमित मात्रा में चीज या घी आ सकता है, लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं। ये ऑफर ट्रंप की टैरिफ नीति का जवाब है, जहां भारत ने कहा कि हम टैक्स कम करेंगे अगर आप भी करें। ग्रीर ने कहा, 'पहली बार इतना अच्छा प्रस्ताव मिला, डील एक साल में हो सकती है।' भारत का मकसद साफ है – अपने किसानों को बचाना, लेकिन व्यापार बढ़ाना। दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक होने के नाते भारत डेयरी बाजार को पूरी तरह नहीं खोलेगा, क्योंकि इससे लाखों परिवार प्रभावित होंगे। लेकिन ये ऑफर रणनीतिक है, क्योंकि अमेरिका के साथ डील से द्विपक्षीय व्यापार 500 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। मोदी सरकार ने GM फसलों पर भी चर्चा शुरू की, लेकिन सुरक्षा जांच के साथ। ये कदम सोच-समझकर उठाया गया, ताकि धार्मिक भावनाएं आहत न हों। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये आधी राह का समझौता चलेगा? अमेरिकी किसान खुश तो होंगे, लेकिन भारतीय बाजार कैसे संभलेगा? ये ऑफर दिखाता है कि भारत अब स्मार्ट डिप्लोमेसी खेल रहा है – न झुकना, न तोड़ना। आगे क्या होगा, ये समय बताएगा।

ट्रंप दूतों की चमकती आंखें: ऑफर से क्यों उछला मन

ट्रंप के दूतों की खुशी छिपी नहीं। जेमिसन ग्रीर जैसे अधिकारी खुलकर बयान दे रहे हैं कि भारत का ऑफर 'गेम चेंजर' है। क्यों? क्योंकि अमेरिकी किसान सालों से भारत जैसे बड़े बाजार की तलाश में हैं। डेयरी एक्सपोर्ट से अमेरिका को अरबों डॉलर का फायदा हो सकता है। ट्रंप ने नवंबर में कहा, 'भारत के साथ नई डील करीब है, टैरिफ कम करेंगे।' दूतों को खुशी इस बात की है कि भारत ने जीरो टैरिफ का संकेत दिया कुछ प्रोडक्ट्स पर। लेकिन असली वजह एग्रीकल्चर ओपनिंग है – सोयाबीन, कॉर्न और सशर्त डेयरी। ट्रंप की नीति 'अमेरिका फर्स्ट' है, और ये ऑफर उसके अनुरूप लगता है। दिसंबर 11 को भास्कर की रिपोर्ट में कहा गया कि दूत मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि डील नजदीक दिख रही है। लेकिन ये खुशी एकतरफा नहीं – भारत को भी फायदा, जैसे टैरिफ हटना और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ग्रीर ने कहा, 'हम रेसिप्रोकल टैरिफ चाहते हैं, भारत ने वो ऑफर किया।' ये दूत ट्रंप के करीबी हैं, जो चुनावी वादों को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या ये खुशी टिकेगी? अगर सर्टिफिकेशन पर अड़ें, तो बात बिगड़ सकती है। ट्रंप ने मोदी को 'दोस्त' कहा, लेकिन व्यापार में दोस्ती टेस्ट होती है। ये खुशी दिखाती है कि कूटनीति में छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं।

संतुलन की तलाश: किसान, भावना और व्यापार का त्रिकोण

भारत-अमेरिका डील के इस चक्रव्यूह में संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। एक तरफ किसानों की आजीविका, दूसरी तरफ धार्मिक भावनाएं, तीसरी व्यापार का लाभ। सरकार तैयार है सशर्त आयात के लिए, लेकिन पूरी तरह बाजार नहीं खोलेगी। विशेषज्ञ कहते हैं कि सर्टिफिकेशन सिस्टम से समस्या हल हो सकती है, लेकिन लागत बढ़ेगी। ट्रंप दूत खुश हैं क्योंकि ये ऑफर उनकी लंबी कोशिशों का फल है। लेकिन भारत को सावधान रहना होगा – सस्ते आयात से अमूल जैसे ब्रांड प्रभावित न हों। 2030 तक 500 अरब व्यापार का लक्ष्य आकर्षक है, लेकिन हानि न हो। ये डील सिखाती है कि वैश्वीकरण में अपनी जड़ें मजबूत रखनी पड़ती हैं। क्या ये समझौता मिसाल बनेगा, या विवाद खींचेगा? समय जवाब देगा, लेकिन उम्मीद है कि दोनों देश जीतें।

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

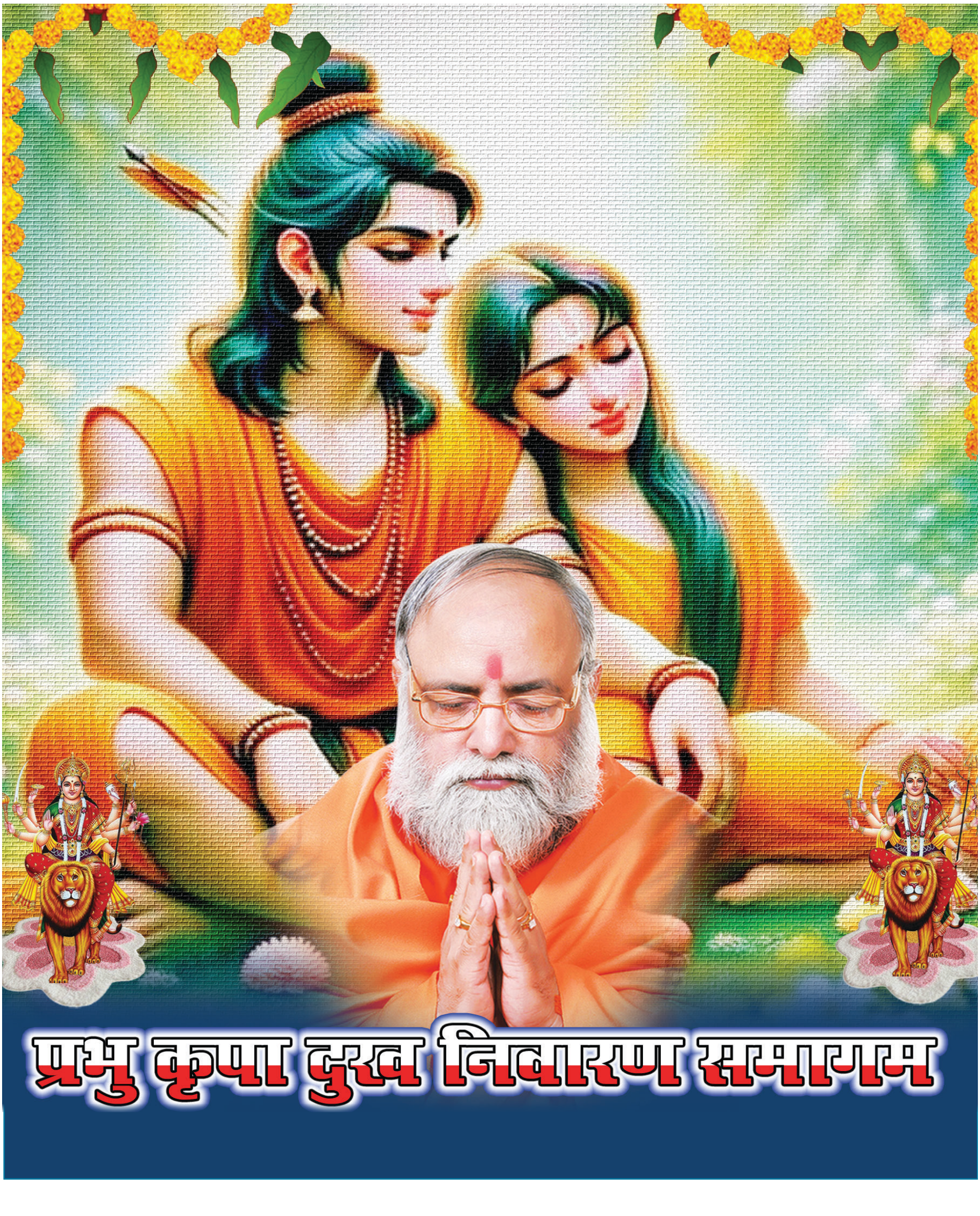

BY

Arihanta Industries

ULTIMATE HAIR SOLUTION

- BHRINGRAJ
- AMLA
- REETHA
- SHIKAKAI

100 ML

15 ML

NO ARITIFICIAL COLOR FRAGRANCE CHEMICAL

KESH VARDAK SHAMPOO

The complete solution of all hair problems:

- Prevent hair fall and make hair follicle strong.
- Promote hair growth.
- Free from all artificial & harmful chemicals like., SLS.
- 100% pure ayurvedic shampoo.
- Suitable for all hair types.

ORDER ONLINE @ :

amazon

arihanta.in

Arihanta Industries